

मग्न के कान्हा में बाधिन और 4 शावकों की मौत में 'केनाइन डिस्टेंपर वायरस' के संकेत

मंडला, 30 अप्रैल 2026। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित देश की शान माने जाने वाले कान्हा टाइगर रिजर्व में बीते नौ दिनों में हुई पांच बाघों (एक बाधिन और उसके चार शावकों) की मौत के मामले में बड़ा संकेत मिला है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में इन मौतों का कारण घातक 'केनाइन डिस्टेंपर वायरस' (सीडीवी) संक्रमण बताया गया है। कान्हा के उप निदेशक प्रकाश कुमार वर्मा ने गुरुवार को बताया कि जबलपुर स्थित स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरसिक एंड हेल्थ में हुए परीक्षणों में वायरस के संकेत मिले हैं। हालांकि, इसकी विस्तृत रिपोर्ट अभी आना बाकी है। गौरतलब है कि कान्हा की प्रसिद्ध बाधिन टी-141 के तीन शावकों की मौत 21 से 25 अप्रैल के बीच हो गई थी। इसके बाद गंधीरूप से बीमार बाधिन और उसके एकमात्र बचे शावक को रेस्क्यू कर मुकुरी क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, लेकिन एक दिन पहले ही यानी बुधवार (29 अप्रैल) को बाधिन टी-141 और उसके चौथे शावक की भी मौत हो गई। पांचों बाघों की मौत के बाद जबलपुर से पशु चिकित्सकों की टीम ने जांच कर परीक्षण के लिए नमूने एकत्रित किए थे। कान्हा के उप निदेशक वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बाधिन और शावकों में केनाइन डिस्टेंपर वायरस के संकेत मिले हैं। यह एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से जंगली मांसाहारी जीवों के श्वसन, पाचन और तंत्रिका तंत्र को निशाना बनाती है। शुरुआत में शावकों के पोस्टमार्टम में पेट खाली मिलने और फेफड़ों में संक्रमण की बात सामने आई थी, जो इस वायरस के प्रमुख लक्षण हैं। यह वायरस बाघों के लिए अत्यधिक जानलेवा माना जाता है।



मल्लिकार्जुन खरगे का दावा-तमिलनाडु व केरल में इंडी गठबंधन की जीत तय

कलबुर्गी, 30 अप्रैल 2026। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडी गठबंधन जीत हासिल करेगा। असम में हमें कम सीटें मिलने का अनुमान एगिजेंट पोल में बताया गया है, लेकिन हम उससे ज्यादा सीटें जीतेंगे। कांग्रेस नेता खरगे यहां कलबुर्गी में पांच रातों के नतीजों को लेकर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए खरगे ने कहा कि वहां तृणमूल कांग्रेस के आगे रहने की संभावना है। एनडीए दलों ने टीएमसी को कड़ी टक्कर दी है, जबकि कांग्रेस इस बार अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा और टीएमसी दोनों ही जीत का दावा कर रही हैं। दो दिन इंतजार कर लें, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पूर्ण नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी को समर्थन देने पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों से जुड़े सवाल पर खरगे ने कहा कि इस मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।



सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

नई दिल्ली, 30 अप्रैल 2026। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। पवन खेड़ा के खिलाफ असम पुलिस ने मानहानि और जालसाजी का मामला दर्ज किया था। यह मामला तब दर्ज किया गया था, जब पवन खेड़ा ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर आरोप लगाए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एसएस चंद्रकर की बेंच ने गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनी। मामले के बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। आगे कोर्ट तय करेगा कि पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं। सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंघवी ने कहा कि पवन खेड़ा पर जो आरोप है, वह शिकायतों की मानहानि करने का है। आरोप सही हैं या नहीं, यह ट्रिब्यूनल में तय होगा। मानहानि के आरोप में पूछताछ की जा सकती है। गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। हालांकि असम सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि पवन खेड़ा ने झूठे दावे करने के लिए पासपोर्ट समेत कई जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। इसलिए, यह पता लगाने के लिए उनकी हिरासत जरूरी है कि इस मामले में उनके साथ कौन-कौन शामिल थे और क्या इसमें कोई विदेशी तत्व भी शामिल है।



देश में एलपीजी की सौ फीसदी आपूर्ति की गई सुनिश्चित, स्टॉक की कमी नहीं : केन्द्र

नई दिल्ली, 30 अप्रैल 2026। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों और मौजूदा संकट के बीच केन्द्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि देश में घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की सप्लाई 100 फीसदी सुनिश्चित की गई है। एलपीजी बुकिंग की अवधि को भी कुशलतापूर्वक मैनेज करने के प्रयास किए गए हैं। इसके साथ ही किसी भी डिस्ट्रिब्यूटर के पास स्टॉक की कमी नहीं है, जबकि आपूर्ति की बिना रुकावट जारी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित अंतर-मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश में घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की सप्लाई सौ फीसदी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि बुकिंग की अवधि को भी कुशलतापूर्वक मैनेज करने के प्रयास किए गए हैं। इसके साथ ही किसी भी एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर के पास स्टॉक की कमी नहीं है और ऑनलाइन बुकिंग लगभग 98 फीसदी तक बढ़ गई है। वहीं, लगभग 93 फीसदी एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी 'डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन कोड' सिस्टम के माध्यम से की जा रही है। सुजाता शर्मा ने बताया कि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई लगभग 70 फीसदी तक बहाल कर दी गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के एजीक्यूटिव डायरेक्टर्स की तीन-सदस्यीय समिति, राज्य सरकारों के समन्वय से कमर्शियल एलपीजी की निरंतर बिक्री सुनिश्चित कर रही है।



मध्यप्रदेश के जबलपुर में कूज डूबा, 6 शव मिले...

15 से ज्यादा लापता, 18 को बचाया, तूफान के चलते नर्मदा के बरगी डैम में हादसा

जबलपुर, 30 अप्रैल 2026। मध्यप्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में गुरुवार शाम पर्यटकों से भरा कूज डूब गया। पुलिस के मुताबिक, 6 शव बरामद किए गए हैं। 18 को सुरक्षित बचा लिया गया।



होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। हालांकि बड़ी टॉच का इस्तेमाल करके लोगों की तलाश की जा रही है।

15 से ज्यादा अब भी लापता हैं। बरगी सिटी एसपी अंजुल मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश टूरिज्म के कूज में 40 से 45 लोग सवार थे। अचानक आई आंधी के कारण ये हादसा हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। अंधेरे

पायलट का दावा : लाइफ जैकेट पहनने का मौका नहीं मिला

कूज पायलट महेश ने बताया कि वह पिछले 10 साल से कूज चला रहा है और पूरी तरह प्रशिक्षित व लाइसेंसधारी है। उनके मुताबिक कूज में सभी सुरक्षा इंतजाम और पर्याप्त लाइफ जैकेट मौजूद थे, लेकिन तूफान इतनी तेजी से आया कि यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनने का मौका नहीं मिल सका।

'सुनामी जैसी हवा वली', 20 साल में पहली बार ऐसा हादसा : एडवाइजर

मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के वाटर टूरिज्म एंड एक्टिविटी एडवाइजर राजेंद्र निगम ने बताया कि बरगी का कूज भोपाल की 'लेक प्रिसेस' की तर्ज पर संचालित होता है और पिछले 20 से अधिक वर्षों से सुरक्षित चल रहा था। उन्होंने कहा, 'अचानक सुनामी जैसी तेज हवा वली, जिसका कोई अंदेशा नहीं था। संचालन से पहले वेदर फोरकास्ट लिया गया था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।'

सुप्रीम कोर्ट बोला...रेप विक्टिम के अबॉर्शन पर टाइम लिमिट हटाएं

केंद्र से कहा...अपने कानून में बदलाव करें, अभी 6 महीने तक गर्भपात का नियम

नई दिल्ली, 30 अप्रैल 2026। सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की रेप विक्टिम को 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में अबॉर्शन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जय्यालक्ष्मी बागची की बेंच ने केंद्र से कहा कि ऐसे मामलों में अबॉर्शन के लिए टाइम लिमिट से जुड़े कानून में बदलाव करना चाहिए। सीजेआई ने कहा, 'कानून ऐसा होना चाहिए, जो समय के साथ बदलता रहे और मौजूदा हालात के अनुसार चले। नाबालिग को जबर्न मां बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में फैसला पीड़ित ही होना चाहिए।' सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को करीब सात महीने प्रेग्नेंट 15 साल की लड़की को अबॉर्शन की इजाजत दी थी। इसके खिलाफ AIIMS ने याचिका लगाई थी। AIIMS ने कहा था कि 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में भ्रूण एक जीव का आकार ले चुका होता है और इस स्टेज पर अबॉर्शन सफल नहीं हो सकता। AIIMS की दलील पर कोर्ट ने कहा कि अगर नाबालिग प्रेग्नेंसी जारी रखती है तो उसे हर दिन मानसिक आघात झेलना पड़ेगा। अभी भारत



वकील ने बताया था-नाबालिग प्रेग्नेंसी से तनाव में है...

24 अप्रैल को सुनवाई में विक्टिम के वकील ने कहा कि इस प्रेग्नेंसी ने नाबालिग को गंभीर मानसिक तनाव दिया है और उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ा है। कोर्ट को बताया गया कि नाबालिग ने पहले से ही गंभीर मानसिक तनाव से संकेत दिखा रहे हैं। वह आत्महत्या की कोशिश भी कर चुकी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि बच्चे को सेंट्रल अर्रॉशन रिसोर्स अथॉरिटी के जरिए गोद दिलाने की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे लड़की और उसके परिवार को प्हावन सुरक्षित रहे।

का कानून रेप मामलों में 6 महीने तक की प्रेग्नेंसी में ही अबॉर्शन की इजाजत देता है।

कोर्ट बोला...महिला को प्रजनन संबंधी फैसले लेने की आजादी : कोर्ट ने कहा, 'किसी महिला, खासकर नाबालिग को इच्छा के खिलाफ प्रेग्नेंसी पूरी करने के लिए मजबूर करना उसके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। इसलिए उसकी इच्छा का सम्मान करना जरूरी है।' कोर्ट ने कहा कि प्रजनन संबंधी फैसले लेने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का हिस्सा है। इसलिए गोद देने का विकल्प किसी महिला को जबर्न बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करने का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर अदालत अनचाही गर्भावस्था को जारी रखने पर जोर देगी तो महिलाएं अवैध अबॉर्शन सेंटरों का सहारा लेने या छिपकर गर्भपात कराने को मजबूर हो सकती हैं। इससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में संवैधानिक अदालतों को यह देखना चाहिए कि गर्भवती महिला के हित में क्या बेहतर है।

ऑपरेशन सिंदूर अपनी मर्जी से रोका न्यूविलियर हमले से नहीं डरे : राजनाथ

नई दिल्ली, 30 अप्रैल 2026। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी मर्जी और अपनी शर्तों पर रोका था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़े तो देश पाकिस्तान के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमले की धमकी दी गई थी, लेकिन भारत इससे नहीं डरा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की सर्ज कैपेसिटी (अचानक ताकत बढ़ाने की क्षमता) पहले से ज्यादा मजबूत है। राजनाथ ने कहा-भारत आज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है जबकि पाकिस्तान को 'आईटी यानी इंटरनेशनल टेरिस्ट' का केंद्र माना जाता है।



राजनाथ बोले- आतंकवाद की जड़ उसकी विचारधारा : सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने दुनिया

नौसेना को मिला 'महेन्द्रगिरी' युद्धपोत, ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती से बढ़ेगी समुद्री क्षमता

नई दिल्ली, 30 अप्रैल 2026। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट्स का आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट 'महेन्द्रगिरी' गुरुवार को मिला गया। मुंबई में मझगांव डॉक शिपविल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) ने आज देश में ही बना चौथा जहाज नौसेना को सौंपा, जिससे भारत की समुद्री ताकत काफी बढ़ गई है। जहाज का नाम ऑडिशा स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत शिखर के नाम पर रखा गया है, जिस पर ब्रह्मोस मिसाइल की भी तैनाती हो सकती है। प्रोजेक्ट 17ए कार्यक्रम के तहत मझगांव डॉक शिपविल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) को चार और गार्डन रीच शिपविल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) को तीन जहाजों का निर्माण सौंपा गया था। इस परियोजना के पहले छह जहाज तारागिरी, उदयगिरि, दूतागिरी,



नीलगिरी, हिमागिरी और विंध्यगिरी 2019-2023 के बीच लॉन्च किए जा चुके हैं। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त को विंध्यगिरी को कोलकाता के गार्डन रीच शिपविल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) में लॉन्च किया था। भारत में पर्वत शृंखलाओं के नाम पर इन सभी

इस्तेमाल सामग्री और उपकरण स्वदेशी वेंडरों से लिए गए हैं और 2000 से अधिक भारतीय प्रतिष्ठानों तथा एमएसएमई में रोजगार सृजन हुआ है। अगस्त 2023 में जहाज की डिलीवरी के लिए एमडीएल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आउटसोर्सिंग से एकीकृत निर्माण पद्धति का उपयोग किया गया है। नौसेना को जहाज की आपूर्ति होने पर एमडीएल के सीएमडी कैप्टन जगमोहन और पूर्वी नौसेना कमान में चीफ स्टाफ ऑफिसर (टेक्निकल) रियर एडमिरल गौतम मारवाह ने नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कागजात पर हस्ताक्षर किए। इस जहाज की आपूर्ति एमडीएल की स्वयंसाधिकाता, विशेषज्ञता और मुश्किल वॉर प्लेटफॉर्म बनाने के अनुभव का सबूत है।

अश्विनी वैष्णव ने जम्मू-कश्मीर रेल नेटवर्क के भविष्योन्मुखी विस्तार की रूपरेखा पेश की

जम्मू, 30 अप्रैल 2026। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर रेल नेटवर्क के भविष्योन्मुखी विस्तार की रूपरेखा भी प्रस्तुत की, जिसमें उच्च तकनीक वाले सिग्नलिंग, उड़ी और पुंछ तक सीमावर्ती कस्बों तक विस्तार और क्षेत्र के प्रतिष्ठित सेब के बागों के संरक्षण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। जम्मू से कटरा तक विस्तारित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए वैष्णव ने कहा कि यात्रियों की भारी मांग के कारण जम्मू-श्रीनगर मार्ग पर 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू की गई है। शुरुआत में कटरा से 8 कोच वाली ट्रेन के साथ संचालित होने वाली यह सेवा जम्मू स्टेशन पर बुनियादी ढांचे के उन्नयन और लगातार पूर्ण क्षमता के कारण अब विस्तारित हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक क्षमता वाली ट्रेन शुरू की गई है। उन्होंने आगे कहा कि अब तक लगभग 55 लाख यात्री 8 डिब्बों वाली वंदे भारत सेवा में यात्रा कर चुके हैं, जो जनता के भारी उत्साह को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे यह नया रेल



संपर्क स्थानीय स्वादों को बढ़ावा देकर और आवश्यक वस्तुओं और ताजे उत्पादों के परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव लाकर क्षेत्र को बदल रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू से यात्रा के दौरान यात्रियों को स्थानीय व्यंजनों से परिचित करने के लिए डोगरी भोजन परसेना है। इसी तरह कश्मीर से रवाना होने वाली ट्रेन में कश्मीरी भोजन उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि इस रेलवे लाइन से माल परिवहन में एक बड़ा बदलाव आया है, जिससे आंटोमोबाल, दोपहिया वाहन, सीमेंट, स्टील, नमक और अन्य सामानों की आवाजाही बेहद आसान हो गई है।

विशेष रूप से श्रीनगर घाटी से देश के बाकी हिस्सों तक लगभग 2 करोड़ किलोग्राम सेब का परिवहन किया जा चुका है। चेरी और सूखे मेवों जैसी अन्य उपज को भी इस परिवहन संपर्क से लाभ हुआ है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर रेल नेटवर्क के भविष्योन्मुखी विस्तार की रूपरेखा भी प्रस्तुत की, जिसमें उच्च तकनीक वाले सिग्नलिंग, उड़ी और पुंछ तक सीमावर्ती कस्बों तक विस्तार और क्षेत्र के प्रतिष्ठित सेब के बागों के संरक्षण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ते हुए विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जम्मू-श्रीनगर रेलवे लाइन की क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें स्वचालित सिग्नलिंग लागू करना शामिल है, जिससे एक ही खंड में एक से अधिक ट्रेनें चल सकेंगी। उन्होंने कहा कि हम बारामूला से उड़ी तक रेलवे लाइन के विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे वहां के निवासियों को काफी लाभ होगा। यह कार्य बंदलाव आया है, जिससे आंटोमोबाल, दोपहिया वाहन, सीमेंट, स्टील, नमक और अन्य सामानों की आवाजाही बेहद आसान हो गई है।

वीआईपी कल्चर छोड़ आम जनता से जुड़े संगठन के नेता : राहुल गांधी

धर्मशाला, 30 अप्रैल 2026। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए वीआईपी संस्कृति छोड़कर आम जनता से सीधे संवाद करना होगा। उन्होंने कांग्रेस के जिलाध्यक्षों से जमीनी मुद्दों को प्राथमिकता देने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नैरेटिव का जवाब मीडिया के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से दिया जाए। राहुल गांधी ने यह बात वीरवार को कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्यों के 80 कांग्रेस अध्यक्षों के ट्रेनिंग शिविर के समापन पर कही। उन्होंने इस दौरान जिलाध्यक्षों को पार्टी को मजबूत करने और आम लोगों से जुड़कर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने के टिप्स दिए। राहुल गांधी ने अपने साढ़े चार घंटे के ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान



संगठन को मजबूत करने, मीडिया प्रबंधन, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग और विपक्ष के नैरेटिव का जवाब देने के भी टिप्स दिए। ट्रेनिंग के जिला अध्यक्षों के साथ लंच किया और दोपहर सवा दो बजे वह कांगड़ा में रखा गया था। इसमें तीन प्रदेशों के 80 जिला अध्यक्षों को 10 दिन तक ट्रेनिंग दी गई।

संपादकीय



केजरीवाल का बिखरता कुजबा

वै कल्पिक राजनीति के सपने दिखाते हुए, चमत्कारिक रफ्तार से दिल्ली और पंजाब की सत्ता कांग्रेस से छीने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के दस राज्यसभा सदस्यों में से सात का भाजपा में शामिल होने का फैसला पार्टी के भटकाव का प्रमाण भी है। हालांकि तीन बागियों ने ही कार्यलय जाकर भाजपा का लड्डू खाया, पर राज्यसभा में आप के नेता संजय सिंह द्वारा उनकी सदस्यता समाप्त के लिए पत्र लिखे जाने के बावजूद सभापति सीपी राधकृष्णन ने सातों बागियों के भाजपा में विलय को मंजूरी दे दी। जाहिर है विभाजन बनाम दलबदल की लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन उससे आप के आंतरिक संकट, असंतोष और बगावत पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। स्वाति मालावाल अरसे से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए थीं तो राघव चड्ढा ने भी राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद खुद को 'घायल' और इसीलिए 'घातक' बताते हुए 'सैलाब' लाने का एलान कर दिया था। इसलिए केजरीवाल के साथ ही उनकी राजनीति को गंभीरता से लेने वालों को भी इस प्रयोग की विफलता का विश्लेषण करना चाहिए। यह भटकाव अचानक नहीं आया।

सत्ता के गलियारों में प्रवेश के साथ ही आप में भटकाव और उसके चलते अलगाव शुरू हो गया था। आप आलाकमान ने पार्टी छोड़ गए संसदों को पंजाब का 'गद्दर' कर दिया, पर यह नहीं बताया कि वे खुद कब और किसके 'वफदार' रहे? राघव, स्वाति और संदीप पाठक को आंदोलनकारी आप का सिपाही मान भी लें तो क्रिकेटर हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और अशोक मित्तल को राज्यसभा सदस्यता किस निष्पक्ष के पुरस्कारस्वरूप दी गई? कभी मोहनलाल सभा की राय से पाण्डे-विधायक प्रत्याशी चुनने की बात करने वाले केजरीवाल ने संसद की उच्च सदन की सदस्यता बांटने की कुछ तो कसौटी रखी होगी।

कारोबारी अशोक मित्तल वही है, जिन्हें केजरीवाल ने राघव को हटाकर राज्यसभा में पार्टी का उप नेता बनाया था, पर दोनों ने ही पांच अन्य के साथ 'झाड़ू' छोड़कर 'कमल' चुन लिया। इनके अलावा भी जो लोग राज्यसभा भेजे गए, उनकी निष्ठा पर लगातार उठते रहे सवालोंने से केजरीवाल फूट चुराते रहे। केजरीवाल को सही आदमी की पहचान नहीं या फिर उनकी कसौटियाँ दल और विचारधारा के प्रति निष्ठा से इतर कुछ और है? खुद को 'ईमानदार' घोषित करते हुए केजरीवाल तमाम परंपरागत दलों और नेताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप-पत्र जारी करते रहे, पर आप में अंतहीन बगावत और अलगाव खुद उन्हें कठबोर में खड़ा करता है। विरोधियों की मानें तो जिस आप को सत्ता राजनीति के चरित्र में बदलाव का वाहक बनाया चाहिए था, वह केजरीवाल की निरंकुश सत्ता का औजार बनकर रह गई। जिस रफ्तार से आप ने दो राज्यों को बसा और राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल किया, उसी गति से उसमें आंतरिक असंतोष उभरता गया। कम उम्र में सीए और फिर विधायक-सांसद बने राघव चड्ढा को जिस तरह राज्यसभा में उपनेता पद से हटाते हुए पत्र लिखा गया कि उन्हें पार्टी की ओर से बोलने का समय न दिया जाए, वह नेतृत्व से बढ़ती कटुता का प्रमाण है। जिन राघव पर पंजाब में 'सुपर सीएम' की तरह काम करने के आरोप लगे, वह अचानक इतना नापसंद कैसे हो गए? क्या निजी रिश्ते ही आप में राजनीतिक हितव्यय तय करते हैं? ऐसे सवाल तभी से उठ रहे हैं, जब दिल्ली में प्रचंड बहुमत से सत्ता मिलने के बाद प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और कुमहार विश्वास जैसे संस्थापक सदस्यों का अलगाव हुआ था, पर जवाब आज तक नहीं मिले।

'आपरेशन लोटस' की भनक मिलने पर ही राघव को उपनेता पद से हटाने की बात कही जा रही है, पर जिन अशोक मित्तल को उनकी कुर्सी दी गई, वह भी भाजपा से जा मिले, शायद ईडी के छापों से डर से। कारोबारी हमेशा मुनाफे का ही सोदा करेगा। केजरीवाल और राघव के बीच दूरियाँ बढ़ने की खबरें अरसे से थीं। जब केजरीवाल कथित शराब घोटाले में जेल भेजे गए, तब राघव आंखों का इलाज कराने लंदन चले गए। जब दिल्ली की एक अदालत द्वारा शराब घोटाले में आरोपमुक्ति पर केजरीवाल ने खुद को फिर 'ईमानदार' घोषित किया, तब भी राघव ने खुशी जताने की जहमत नहीं उठाई। आप के मुखर नेता रहे संदीप पाठक द्वारा भाजपा में जाना चीकता है, पर केजरीवाल के राजनीतिक प्रबंधन पर सवालिया निशान भी लगाता है। यह नसीहत स्वाभाविक है कि आप छोड़ने वालों को राज्यसभा सदस्यता भी छोड़ देनी चाहिए, पर जब राजनीति का लक्ष्य ही सत्ता है तो उसे पाने के बाद कौन छोड़ देगा? दूसरों को आरोप लगते ही पदत्याग की नसीहत देने वाले केजरीवाल जेल जाने के बाद भी लंबे समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे थे जबकि उसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के साथ ही इस्तीफा देकर अलग मिसाल पेश की थी। विधानसभा चुनाव होने पर दोनों राज्यों के मतदाताओं ने भी अलग-अलग जनादेश दिया। आप में टूट से राज्यसभा में भाजपा के लिए बहुमत की राह आसान होगी, पर उसका लक्ष्य पंजाब और गुजरात है। गुजरात में भाजपा के दशकों से बढबढ़े के चलते तात्कालिक चुनौती नहीं, पर 13 के पार पहुंच गया आप का मत प्रतिशत खरते का संकेत है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ भाजपा का गठबंधन विजयी समीकरण था, लेकिन अलगाव के बाद दोनों हाशिए पर चले गए। आप प्रचंड बहुमत से सत्ता में है तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष क्रमशः कैटन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ भाजपा में आ चुके हैं। पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पौत्र रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा से लोकसभा तो नहीं पहुंचे, पर राज्यसभा के रास्ते केंद्रीय मंत्री बना दिए गए। आप छोड़ भाजपाई बने राज्यसभा सदस्यों में से किसी का भी जनाधार नहीं, लेकिन उनके जरिये आप में बड़े विभाजन से विधानसभा चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार खतरे में पड़ी तो भाजपा का राजनीतिक स्थिरता का कार्ड चल सकता है। दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता भी हाथ से फिसलना केजरीवाल और आप के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा सवालिया निशान होगा।



प्रोफेसर शामलाल कोशल
रोहतक, हरियाणा

उत्पादन के चार साधन होते हैं... भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। लेकिन इन चारों में श्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि श्रमिक ही अपने परिश्रम के द्वारा भूमि का प्रयोग करता है, पूंजी का संयोज करता है तथा उद्यमकर्ता का निर्माण करता है। किसी भी देश का विकास उसे देश में उपलब्ध श्रमिकों की मात्रा, उनके प्रशिक्षण, ज्ञान तथा कार्य कुशलता पर निर्भर करता है! संभवतः यही कारण है कि विश्व के अधिकांश भागों में 1 मई को राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। असल में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने की परंपरा अमेरिका से हुई जब कुछ मजदूर संघों ने दिन में ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे काम करने और इससे ज्यादा काम करने के लिए ओवरटाइम की मांग की। तभी से विश्व के अधिकांश देशों में 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस



मनाया जाने लगा है। मजदूर दिवस मनाए जाने के पीछे मजदूरों की अपनी कुछ जायज मांगें मनवाना है जैसे उचित मजदूरी दी जाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना कराया जाए, 8 घंटे से ज्यादा काम कराए जाने पर ओवरटाइम दिया जाए, सप्ताह में एक दिन वेतन सहित छुट्टी दी जाए, दुर्घटना या मृत्यु होने पर उचित मुआवजा दिया जाए, काम करने के स्थान को सुरक्षित बनाया जाए, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, संतान होने के समय महिला श्रमिकों को वेतन तथा चिकित्सा सुविधा समेत छुट्टी दी जाए, सेवानिवृत्त होने पर प्रोविडेंट फंड तथा ग्रेज्युटी दी जाए, छटनी ना की जाए।

निक्लते हैं, भाषण देते हैं, स्मरण पत्र,, मेमोरेंडम देते हैं। यहां यह बातना है अप्रासंगिक नहीं होगा कि श्रम दिवस के जनक पीटर मैककार्थर तथा मैथ्यू मैयुअर नाम के दो व्यक्ति थे।

आमतौर पर अपनी मांगों को बनवाने के लिए मजदूर लोग मजदूर संघ या ट्रेड यूनियंस बनाते हैं। मजदूर संघ मजदूरों के द्वारा स्वैच्छिक तौर पर उनकी मांगों को मालिकों से मनवाने की एक संस्था होती है। वह दो प्रकार के काम करती है... संघर्ष आत्मक तथा कल्याणकारी...! संघर्ष आत्मक कार्यों में मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल करना, जुलूस निकालना, धरना देना, बाईकाट करना शामिल होते हैं। जबकि कल्याणकारी कार्यों में मजदूरों के रहने के लिए व्यवस्था करना, शिक्षा तथा चिकित्सा का प्रबंध करना आदि शामिल

होते हैं। समय-समय पर श्रम संघों तथा मिल मालिकों में बातचीत होती रहती है और उचित मांगें बिना किसी तकरार के मान ली जाती हैं। कई बार मजदूरों को मालिक औद्योगिक इकाई के प्रबंध में भी शामिल कर लेते हैं। अगर कभी मजदूर तथा मिल मालिकों में उपर्युक्त बातों में से किसी बात पर सहमति नहीं होती तो इसे निपटाने के लिए त्रिपक्षीय समितियाँ होते हैं, जिनमें मिल मालिक, श्रमिकों तथा सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस प्रकार की त्रिपक्षीय समितियाँ जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर होती हैं। इसके अलावा श्रम न्यायालय भी है। यहां यह जानना दिलचस्प होगा की 1917 में जब रूस में क्रांति आई तब वहां पर श्रमिकों की सरकार बनी थी जिसे गर्वमेंट ऑफ द प्रोलेटरियट कहते हैं। 1924 में इंग्लैंड में पहली बार लेबर

श्रमिकों के संघर्ष के विजय का पावन दिन



प्रमोद दूत मिश्र
बांदा, उत्तरप्रदेश

धर के सौन्दर्य का आधार श्रम है। श्रम-श्रेय से सिंचित वसुधारा में स्वप्नों के विविध रंग अपनी आभा के साथ प्रकट होकर जन-जन को प्रसन्नता की पूंजी बांटते हैं। मनुष्य का श्रम ही जीवन के कर्म पथ के कष्ट कंटकों को चुनकर उस पर सुवासित सुमन बिखेरता है। दुनिया की गतिशीलता का ईश्वर श्रम है, जो श्रमिक के अनवरत जीवन संघर्ष से उपजता है। श्रमिक ही अपनी मेहनत से बंजर धरती को हरीतिमा का फलक प्रदान करता है, अथाह सिंधु जल में गोता लगा मुक्ता-मूर्तियों का ढेर जग की झोली में उछल देता है। वही वह महत्त्वपूर्ण व्यक्ति है जो एक-एक इंटर जोड़कर भव्य प्रासाद का निर्माण कर देता है। श्रमिक ही है जो काल के वक्षस्थल पर रैखकर जन सामान्य के लिए सुख-सुविधा के तमाम संसाधन सुलभ कराता है। वही है जो संतोष के धन से समृद्ध

है, आबाद है। अपनी टूटी झोंपड़ी में हर कर रुखा-सूखा खाकर भी वह लोक कल्याण के लिए अर्हर्निश बद्धपरिकर हो श्रम-संलग्न रहता है। पर संसार की श्रुधा शान्त करने वाला भूखा है, अर्थव्यवस्था है। महल निर्मित करने वाला कुशल कामगार कुटीर वासी है, क्यों? आखिर क्यों पृथ्वी दुनिया में 1 मई मजदूर दिवस के रूप में मनाकर उसके उत्थान की बातें की जाती हैं लेकिन मजदूर की किस्मत नहीं बदलती। वह पूंजी के पाटों के बीच फंसा छटपटा रहा है।

संगठन के स्तर पर दो प्रकार के मजदूर वर्ग सामने दिखाई पते हैं। पहला संगठित और दूसरा असंगठित। सबसे बुरी स्थिति इसी दूसरे असंगठित मजदूर वर्ग की है। संगठन और संघर्ष नेतृत्व के अभाव में ये अपनी बात मालिक तक पहुंचा नहीं पाते। इनका शोषण भी बहुत होता है। चाहे वह श्रम के रूप में हो या मजदूरी में मिलने वाली राशि के रूप में। पहला मजदूरों की स्थिति तो और भी दयनीय है। उनसे भरपूर और पुरखों के बराबर काम तो लिया ही जाता है पर पजदूरी पुरुष कामगार हुए। इनकी शुरुआती मांग थी कि काम के 12-16 घण्टों को घटाया और निश्चित किए जाएं। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी भी मिलनी चाहिए। इन्हें आन्दोलनों और मजदूर वर्ग में आयी जागरूकता का ही प्रभाव था कि

1835 तक कई देशों के मजदूरों ने 10 घण्टे प्रतिदिन काम का अपना हक प्राप्त कर लिया था। 1860 तक अमेरिका में भी 10 घण्टे का कार्य दिवस निश्चित कर दिया गया। पहली मजदूर राजनीतिक पार्टी 1828 में फ्लोराडेल्फिया में बनी जिसके घोषणा पत्र में 10 घण्टे का कार्यदिवस करने, सेना में अनिवार्य सेवा की समाप्ति, मजदूरी मुद्रा में देने, बच्चों की शिक्षा, कर्जदार मजदूरों के लिए दी जाने वाली सजा को समाप्त करने जैसे बुनियादी मांगों शामिल थीं; जो धीरे-धीरे मानी भी गईं। कुछ मजदूर यूनियनों ने अपना अखबार भी निकाला और हड़ताल करने के लिए स्थायी कोष की भी व्यवस्था की। 7 सितम्बर, 1883 सितम्बर के पहले सोमवार को पहली बार मजदूर छुट्टी दिवस मनाया गया। शिकागो (अमेरिका) में 1 मई, 1886 को बहुता बड़ी मजदूर हड़ताल हुई, जिसमें 8 घण्टे का कार्य दिवस करने और सप्ताह में एक दिन की अनिवार्य छुट्टी देने की मांग की गई। उसी का परिणाम है कि विश्व में प्रत्येक दूकान-संस्थान में आज एक दिवसीय साप्ताहिक अवकाश की वैधानिक व्यवस्था है। भारत में पहली बार मजदूर दिवस 1 मई, 1923 को मद्रास (अब चेन्नै) में मनाया गया।

कंधों पे सपनों का भार...



संजय एम तरापोकर
इन्दौर, मध्य प्रदेश

सुबह की पहली किरण संग, कंधों पे सपनों का भार, चल पड़ता है वह चुपचाप, रचने दुनिया हर एक बार। हथों में मेहनत की रेखा, बड़े पसीना उसकी पहचान, ईंट-पत्थर में बसती है, उसकी हर अधूरी-सी मुस्कान।

धूप में जल रहे उसके अरमान, छव में भी ना आराम, रोटी, कपड़ा और मकान, बस इतना-सा उसका धाम। ऊँची-ऊँची इमारतें बोलती, उसकी खामोश है कहानी, हरेक मजिल में गुंज रही है, उसकी मेहनत की रवानी।

मजदूर



प्रीतम कुमार
साहू,
लियातपुर,
धमतरी
छत्तीसगढ़



मजदूर है, मजबूत है, मजबूर नहीं ! दिन रात वह मेहनत करता है ! चैन सुकून से वह रहता है ! पसीने की कमाई वह खाता है ! गीत खुशी के वह गाता है ! मजदूर है, मजबूत है, मजबूर नहीं ! माना साधन उनके पास भरपूर नहीं ! औरों से वह मशहूर नहीं ! कंधे पर बोझ वह ढोता है ! अपनी हालत पर वह नहीं रोता है ! मजदूर है, मजबूत है, मजबूर नहीं ! परिवार का पोषण करता है ! नाम मालिक का रोशन करता है ! नाम अपना वह छिपाता है ! आँसू वह नहीं बहाता है ! मजदूर है, मजबूत है, मजबूर नहीं !



सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटीक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

अशांति से शांति की ओर यात्रा ही है बुद्ध का मार्ग

योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़, नई दिल्ली



अंधकार से प्रकाश की ओर : बुद्ध पूर्णिमा का जीवन-दर्शन
प्रतिवर्ष वैशाख मास की पूर्णिमा को 'बुद्ध पूर्णिमा' के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा इस वर्ष 1 मई को है। माना जाता है कि 563 ई.पू. वैशाख पूर्णिमा के ही दिन लुम्बिनी वन में शाल के दो वृक्षों के बीच गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्होंने वैशाख पूर्णिमा को ही बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त किया था। यही कारण है कि बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा को सबसे पवित्र दिन माना गया है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। गौतम उनका गौत्र था किन्तु कालांतर में वह सिद्धार्थ गौतम, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, तथागत आदि विभिन्न नामों से कभी भी नामों से ही राजकुमार सिद्धार्थ घंटों एकांत में बैठकर ध्यान किया करते थे लेकिन फिर भी उन्होंने पुत्र जन्म तक सांसारिक सुखों का उपभोग किया परन्तु धीरे-धीरे उनका मन सांसारिक सुखों से उचाट होता गया।

दशा है? 'सारथी ने बताया, 'यह भी एक मनुष्य है और इस समय यह बीमार है। इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी रोगी होकर दुःखों का सामना करना ही पड़ता है।'

आगे बढ़ने पर सिद्धार्थ ने मार्ग से गुजरते एक वृद्ध, निर्बल व कृशकाय व्यक्ति और उसके बाद एक मृत व्यक्ति की अर्थात् ले जाते विलाप करते लोगों को देखा तो हर बार सारथी से उसके बारे में पूछा। सारथी ने एक-एक कर उन्हें मनुष्य की इन चारों अवस्थाओं के बारे में बताया कि हर व्यक्ति को कभी न कभी बीमार होकर कष्ट झेलने पड़ते हैं। बुढ़ापे में काफी दुःख झेलने पड़ते हैं, उस अवस्था में मनुष्य दुर्बल व कृशकाय होकर चलने-फिरने में भी कठिनाई महसूस करने लगता है और आखिर में उसकी मृत्यु हो जाती है।

नींद में सोता छोड़ उठनें घर-परिवार और राजसी सुखों का परित्याग कर दिया तथा सत्य एवं जान की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे। उन्होंने छह वर्षों तक जंगलों में कठिन तप किया और सूखकर कांटा हो गए किन्तु ज्ञान की प्राप्ति न हो सकी। उसके बाद उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक शक्ति प्राप्त की और बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गहन चिंतन में लीन हो गए तथा मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस बार ज्ञान प्राप्त किए बिना वे यहां से नहीं उठेंगे।

सात सप्ताह के गहन चिंतन-मनन के बाद वैशाख मास की पूर्णिमा को 528 ई.पू. सुनोदय से कुछ पहले उनकी बोधवृष्टि जागृत हो गई और उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनके चारों ओर एक अलौकिक आभा मंडल दिखाई देने लगा। उनके पांच शिष्यों ने जग यह अनुभव दृश्य देखा तो उन्होंने ही राजकुमार सिद्धार्थ को पहली बार 'तथागत' कहकर संबोधित किया। 'तथागत' यानी सत्य के ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति करने वाला। पीपल के जिस वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त किया, वह वृक्ष 'बोधिवृक्ष' कहलाया और वह स्थान, जहां उन्होंने यह ज्ञान प्राप्त किया, बोध गया के नाम से विख्यात हुआ तथा बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद ही सिद्धार्थ को 'महात्मा बुद्ध' कहा गया। महात्मा बुद्ध मन की साधना को ही सबसे बड़ी साधना मानते थे। अपने 80 वर्षीय जीवनकाल के अंतिम 45 वर्षों में उन्होंने दुनियाभर में घूम-घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और लोगों को उपदेश दिए।

श्रममेय जयते! का यशोगान

हेमेट्ट क्षीरसागर
बालावाट, मध्यप्रदेश



हां! मैं हूँ मजदूर, मजदूर ही रहूँगा और मजदूर ही मरूँगा यह करुणा आज भी झेंझोर कर शर्मसार करती है। ग्लानि इस मर्ज का मर्म आखिर क्यों नहीं ढूँढ पाए। समझ से परे है। साधन, संसाधन और संपन्नता में कोई कमी नहीं है। फिर मजदूरों का ये हाल कैसा? क्यों हमारा श्रम रोटी-कपड़ा-मकान और कमाई-पहवाई-दवाई की झंझावात में उलझता है? क्या मजदूर जैसा पैदा होता है वैसा ही मर जाए? हरगिज भी नहीं! मजदूरों को उनका वाजिब हक और अधिकार मिलना चाहिए, जिसके बाद ही हकदार है। अभिलाषा, समृद्ध श्रम नीति सुदृढ़ राष्ट्र क्रांति का अनुष्ठा करनी। कर्मवीरता में राष्ट्र का विकास और जन-जन का कल्याण निहित है। आइए, हम सब मिलकर मैं मजदूर हूँ, मैं मजबूत हूँ के श्रामोभय से राष्ट्रीय दाय को और आगे बढ़े।

मजदूर आज मजबूर
आगर हम बात करें तो मानव शक्ति, दिगम्गी कार्य, शारीरिक बल और प्रयास करने वाला। काम को मेहनत के द्वारा अपनी श्रम शक्ति को बेचें, उसी का नाम मजदूर है। मजदूर ही देश के विकास की रीढ़ की हड्डी। मजदूर के पसीने से मूलक लहलहाता है। सही मायनों में कहे तो मजदूर ही भाग्य विधाता है। अलबत्ता भाग्य विधाता ही अपने भाग्य को खोज रहा है? मजदूर आज मजबूर बनकर कर्मपथ पर चलकर मन लक्ष्यपथ हो रहा है। इसके कारण और कारक किसे माने सरकारें, नियत,

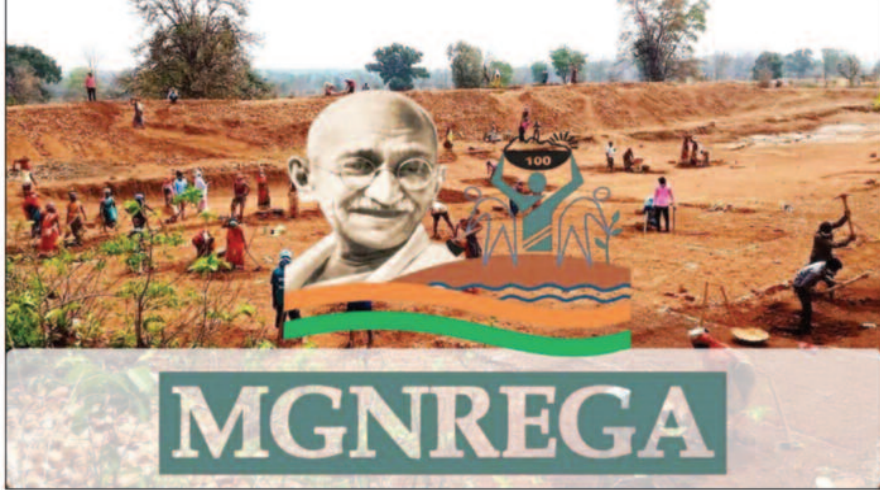
श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 इत्यादि उद्योग तथा श्रम सम्बन्धी विधान की श्रेणी में आते हैं। हमारे संविधान में मजदूर को सम्मान जनक काम और मजदूरी देने के साथ-साथ कानूनी संरक्षण दिया है। काम का अधिकार और पूरी मजदूरी देने का प्रावधान कर शोषण से बचाने के लिए अलग से ही श्रम विधि का गठन कर शोषण कर्ता को दंड का प्रावधान भी किया गया है। अब कोई भी नियोजित ठेकेदार, कारखाना मालिक मजदूरों का शोषण नहीं कर सकता है। जो उनकी नॉटिस बोर्ड तक ही सीमित दिखाई पड़ता है। इसे धरातल पर लाना होगा।

कोई सुध ले ले
बाकायदा, अर्धकुशल-अकुशल, कुशल-उच्च कुशल, दैनिक वेतन भोगी-संविदा कर्मी, अस्थाई-स्थाई, आउटसोर्सिंग-ठेकेदारी भांति-भांति के फेर में अल्प वेतन और नियमितिकरण की भेंट चढ़ना हमारे मजदूरों की फितरत बन गई है। वह जैसा था, आज वैसा ही है, ये वाजिब नहीं है। वह सामान्य कार्य-सम्मान वेतन। सम्मान सुस्था, सुविधाएं और न्याय की मांग करते-करते थक गया। धरना, प्रदर्शन, आंदोलनों और रैलियों में इनकी ऊर्जा नष्ट हो गई। बजाए कोई सुध ले। एक मजदूर, मजबूत भार होकर भी मजबूर हो गया। कमशकम इन्हें जियो और जीने दो का अधिकार तो मिलना चाहिए, क्योंकि श्रमशक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है। तभी श्रमोभय से राष्ट्रीय की अभिकल्पना साकार होगी। यथेष्ट, श्रममेय जयते! का यशोगान जन-गण में होगा। अन्यथा श्रम तार-तार होता रहेगा!

मजदूर दिवस विशेष :संघर्ष की जीत,पसीने का सम्मान! कोरिया जिले में लौटे 'अच्छे दिन': लंबित मजदूरी और पेंशन के भुगतान से वनांचल में हर्षोल्लास



मजदूर दिवस से पूर्व ही बकाया मजदूरी भुगतान और पेंशन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लौटी रौनक



सामाजिक सुरक्षा को मिला नया संबल



खोखले दावों के बीच सुलभता आक्रोश
जनवरी से लंबित मजदूरी भुगतान ने तोड़ी मजदूरों की कमीर
वनांचल क्षेत्रों में आर्थिक संकट

कहते हैं कि मजदूर का पसीना सुखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर और सोनहत ब्लॉक के हजारों मजदूरों और बुजुर्गों के लिए इस बार का 'मजदूर दिवस' (1 मई) महज एक तारीख नहीं, बल्कि उनके स्वाभिमान और संघर्ष की जीत का उत्सव बनकर आया है, जनवरी से लंबित मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कारण जो घर अब तक मायूसी के साये में थे, वहाँ अब खुशहाली की नई इबारत लिखी जा रही है।

इच्छाशक्ति से मिला आर्थिक 'सूखा'
बीते चार महीनों से कोरिया जिले के वनांचल क्षेत्रों में आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे थे, होली और नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार तंगी की भेंट चढ़ गए थे, लेकिन शासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस गतिरोध को खत्म किया, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय का ही सुखद परिणाम है कि जनवरी से मार्च तक का पूरा बकाया मजदूरी भुगतान अब क्लियर हो चुका है मजदूरों की राशि सीधे मजदूरों के खातों में पहुंचने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में फिर से जान आ गई है।

सामाजिक सुरक्षा को मिला नया संबल
इस सकारात्मक बदलाव का सबसे बड़ा असर समाज के सबसे कमजोर वर्ग पर पड़ा है। जिले के हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि मिल गई है। पेंशन की यह राशि खातों में आने से उन बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को सबसे बड़ी राहत मिली है, जो अपनी बुनियादी जरूरतों और दवाइयों के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब उन्हें अपनी छोटी-मोटी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की मजबूरी नहीं रही।

प्रशासनिक मुस्तैदी और स्थानीय बाजार में रौनक
इस समाधान के पीछे विधानसभा में उठे मुद्दों और विभागीय मंत्री विजय शर्मा की केंद्रीय स्तर पर की गई प्रभावी पैरवी का बड़ा हाथ रहा। प्रशासनिक मुस्तैदी का ही असर है कि तकनीकी खामियों को रिक्तों समय में दूर कर भुगतान सुनिश्चित किया गया, इसका सीधा असर स्थानीय बाजारों में भी देखने को मिल रहा है; आर्थिक तरलता बढ़ने से छोटे दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं और ग्रामीणों ने अपने पुराने कर्ज चुकाकर चैन की सांस ली है।

पसीने की हर बूंद की कीमत
आज मजदूर दिवस के गौरवशाली अवसर के पूर्व ही, कोरिया जिले के इन कर्मयोगियों के खातों में आई उनकी मेहनत की कमाई उनके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आई है, यह जीत उन हाथों की है जो पत्थर तोड़कर विकास की राह बनाते हैं, शासन की इस त्वरित कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि पसीने की हर बूंद की कीमत होती है। मजदूर दिवस पर उन सभी कर्मठ हाथों को सलाम, जिनके परिश्रम से राष्ट्र का निर्माण होता है!

घटती-घटना ने उठाया था मामला
इस पूरे घटनाक्रम में 'घटती-घटना' समाचार पत्र की सजम पत्रकारिता अहम रही, जब वनांचल क्षेत्रों में मजदूर और बुजुर्ग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, तब 'घटती-घटना' ने इस गंभीर मुद्दे को पूरी प्रमुखता और संवेदनशीलता के साथ प्रकाशित किया था। समाचार पत्र ने न केवल प्रशासन को उजागर किया, बल्कि मजदूरों के घर के चूल्हे बुझने की कड़वी हकीकत को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया। खबर के प्रकाशित होने के बाद ही विभागीय मशीनरी सक्रिय हुई और शासन-प्रशासन पर त्वरित भुगतान के लिए दबाव बढ़ा। यह सफल परिणाम दर्शाता है कि जब मीडिया जनता की आवाज बनता है, तो व्यवस्था को झुकना पड़ता है और अंतिम व्यक्ति को उसका हक मिलकर रहता है।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने सुलझाए लंबित प्रकरण



एक वर्ष से लंबित अमानत राशि का हुआ भुगतान, फोरम ने देरी पर अधिकारियों को ही हिदायत

संवाददाता- अम्बिकापुर, 30 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी नीतियों और विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की सक्रियता से जिले के विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल रही है। फोरम की हालिया सुनवाई में न केवल वर्षों पुराने भारी-भरकम बिजली बिलों का निपटारा किया गया, बल्कि लंबित अमानत राशि (सिक्वोरिटी डिफॉलिट) का भुगतान भी सुनिश्चित कराया गया। एक अन्य प्रकरण में, अम्बिकापुर संभाग के जोन-तीन (जेल कॉलोनी) निवासी श्री रमेश गिरी को एक वर्ष से लंबित अमानत राशि का निराकरण किया गया। फोरम के हस्तक्षेप के बाद विभाग ने 2,570 रुपये की अमानत राशि सीधे उपभोक्ता के भारतीय स्टेट बैंक के खाते में हस्तांतरित कर दी है। हालांकि, इस छोटे से प्रकरण में हुए एक वर्ष के विलंब पर फोरम ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सहायक यंत्री श्री अभिनेश बंजारे की उपस्थिति में फोरम ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि भविष्य में उपभोक्ताओं से जुड़े कार्यों में समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए ताकि आम नागरिकों को मानसिक व आर्थिक परेशानी न हो।



प्रधान पाठक सोनसाय हुए सेवानिवृत्त, दत्तनकरा स्कूल में भव्य सम्मान के साथ दी गई भावभीनी विदाई

संवाददाता- सूरजपुर, 30 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
विकासखंड प्रतापपुर अंतर्गत दत्तनकरा स्थित प्राथमिक पाठशाला में लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधान पाठक सोनसाय के सेवानिवृत्त होने पर विद्यालय परिसर में भव्य विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद करते हुए कार्यक्रम को उत्सव का रूप दिया गया, जिसमें आसपास के स्कूलों के शिक्षक एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रधान पाठक के रूप में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान सोनसाय ने अनुशासन, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर उनके उज्वल भविष्य की नींव रखी। समारोह में उपस्थित वक्ताओं ने उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा विद्यार्थियों के हित को सर्वोपरि रखा और अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। विदाई समारोह के दौरान शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। कई शिक्षकों ने अपने उद्बोधन में कहा कि सोनसाय के मार्गदर्शन से उन्हें प्रेरणा मिली और उनके कार्यशैली से सीखने को बहुत कुछ मिला। इस अवसर पर सोनसाय ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना उनके लिए गर्व का विषय रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का सम्मान उनके जीवन का अविस्मरणीय पल है, जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। कार्यक्रम में विकासखंड शिक्षा अधिकारी मूनू सिंह धुवे सहित अनेक शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। वक्ताओं ने कहा कि यह केवल विदाई नहीं, बल्कि एक ऐसे शिक्षक के योगदान का सम्मान है, जिसने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया समारोह में मौजूद रहे प्रधान पाठक अनीता, गीता बेक, विजय पटेल, प्रफुल्ला कुजूर, उमा पांडे, कामेश्वर सिंह, रामखेलावन, इंद्रबली कुशवाह, डब्ल्यू राम पैकरा, कमलेश भागवत, सुशील कुमार, सरिता राम, राकेश कुमार गुप्ता, प्रदीप सिंह, अनुपा मिंज, निराली खलको, रमेश शर्मा, कुपारंकर, धनेशराम, सुकृता कंवर, क्षमता मिश्रा, सत्यमा एक्का, दीपमाला, राधिका शरण सिंह विदाई समारोह में उपस्थित रहे।

अम्बिकापुर में नशीले इंजेक्शन पर बड़ी कार्रवाई, 396 इंजेक्शन जब्त 3 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार, लघुशंका के बहाने टीम को दिया चकमा

संवाददाता- अम्बिकापुर, 30 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
संभागीय आबकारी उद्वेगदाता टीम ने नशीले इंजेक्शन के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपियों के कब्जे से कुल 396 नग नशीले इंजेक्शन जब्त किए हैं। एक आरोपी कार्रवाई के दौरान फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि 29 अप्रैल को मुखबिर् की सूचना पर गांधीनगर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई में करार (थाना राजपुर, जिला बलरामपुर) निवासी अश्वयुजसवाल को आसखंड-चंघरी बाजार के पास पकड़ा गया। उसके पास से 120 नग रेक्सोजेसिक और 120 नग एवील इंजेक्शन जब्त किए गए, जिनकी कीमत करीब 1.20 लाख रुपए आंकी गई है।

कार्रवाई के मकान में दबिश : दूसरी कार्रवाई में सरगावां क्षेत्र में कार्रवाई के मकान में रहने वाले ओम उर्फ शौर्य पाठक को पकड़ा गया। उसके पास से 38-38 नग रेक्सोजेसिक और एवील इंजेक्शन जब्त किए गए, जिनकी कीमत करीब 38 हजार रुपए बताई गई है।

आरोपी ने भागकर दिया चकमा : कार्रवाई के दौरान आरोपी ओम पाठक लघुशंका का बहाना बनाकर टीम को चकमा देकर फरार हो गया। उसकी तलाश में जुटी टीम ने देर रात पीजी कॉलेज मैदान के पास दो सदिध युवकों को पकड़ा। तलाशी लेने पर उनके पास से 40-40 नग रेक्सोजेसिक और एवील इंजेक्शन बरामद हुए, जिनकी कीमत करीब 40 हजार रुपए है।

दो और आरोपी गिरफ्तार : मामले में राजपुर (जिला बलरामपुर) निवासी विवेक सोनी और प्रिंस एक्का को गिरफ्तार किया गया है।



एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई : आबकारी टीम ने गिरफ्तार तीन आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 (सी) के तहत कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया है। फरार आरोपी ओम पाठक की तलाश जारी है।

3 मई को दोपहर 2 से 5 बजे शाम तक आयोजित होगी नीट-यूजी परीक्षा

परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र स्थल एवं समय का रखे विशेष ध्यान
संवाददाता- अम्बिकापुर, 30 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
कलेक्टर श्री अजीत वसंत की अध्यक्षता में आगामी 3 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 के सफल, निष्पक्ष और सूच्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने सूक्षा से लेकर मूलभूत सुविधाओं तक परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी, सुनिश्चित वातावरण में संपन्न करने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं केंद्राध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने एनटीए के निर्देशों का पालन करते हुए संवेदनशील मामलों में विशेष ध्यान रखते हुए सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न करने के निर्देश दिए। अम्बिकापुर में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 4939 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उन्होंने परीक्षा सामग्री को पूरी सावधानी एवं सतर्कता के साथ परीक्षा केंद्रों में सूक्षा बल के साथ समय पर पहुंचने के निर्देश दिए। परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे तक आयोजित होगी।

वीडियो शूटिंग करने गया युवक... लौटकर देखा तो बाइक गायब, 3 घंटे की पड़ताल के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता- अम्बिकापुर, 30 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
शहर के मणिपुर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, रितिक रोशन ठाकुर निवासी महामाया तालाब के पास, महामायापारा अम्बिकापुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 27 अप्रैल 2026 की रात करीब 8 बजे अपनी सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक CG 15 DX 9052 से हरी मंगराम होटल के सामने पहुंचा था। बाइक खड़ी कर वह वीडियो शूटिंग करने चला गया। रात करीब 11:30 बजे वापस लौटने पर देखा कि उसकी मोटरसाइकिल मौके से गायब थी। इसके बाद उसने थाना मणिपुर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 77/2026 के तहत धारा 305 (बी) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तथा सदिधों की तलाश में मुखबिर् तंत्र सक्रिय किया। जांच के दौरान सूचना मिली कि राजू नोसिया, दिव्यांशु बघेल और विजय कुमार सोनकर ने मिलकर 27 अप्रैल को बाइक चोरी की है। सूचना के बाद पुलिस टीम ने तीनों के ठिकानों पर दबिश दी और हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल क्रमांक CG 15 DX 9052 बरामद कर ली।

गिरफ्तार आरोपी : विजय कुमार सोनकर, उम्र 20 वर्ष, निवासी घुटारापारा, थाना मणिपुर, अम्बिकापुर दिव्यांशु बघेल, उम्र 18 वर्ष, निवासी बिहीबाड़ी, थाना मणिपुर, अम्बिकापुर राजू नोसिया, उम्र 19 वर्ष, निवासी जिला अस्पताल के पास, दर्रापारा, अम्बिकापुर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका : पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक सी. पी. तिवारी, सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, प्रधान आरक्षक विजय रवि तथा आरक्षक उमाशंकर साहू, सत्येंद्र दुबे, रामाशंकर यादव, रमेश राजवाड़े, जितेश साहू और सैनिक दिनेश यादव सक्रिय रहे।

भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए दाना-पानी रख मानवता का संदेश दे रहे कमलेश योगी

पतंजलि योग समिति के सह राज्य प्रभारी ने पर्यावरण संरक्षण और जीव सेवा का दिया संदेश
संवाददाता- अम्बिकापुर, 30 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।
पतंजलि योग समिति छत्तीसगढ़ के सह राज्य प्रभारी कमलेश योगी द्वारा भीषण गर्मी के बीच पक्षियों और मूक प्राणियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था कर प्रेरणादायक पहल की जा रही है। उनकी इस सेवा भावना की क्षेत्र में सराहना हो रही है। कमलेश योगी का कहना है कि जिन जीवों के पास अपनी पीढ़ी और भावना व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं, उनकी सहायता करना मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे जीव-जंतुओं और पक्षियों की समस्याओं को समझते हुए उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करना अत्यंत पुण्य कार्य है। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में पेड़-पौधे, पशु-पक्षी और समस्त जीव-जगत की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो भूकंप, सुनामी, महामारी, आंधी-तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। इसलिए प्रकृति और जीव-जंतुओं की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस भीषण गर्मी में अपने घरों, छतों, आंगनों और सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों के लिए पानी के बर्तन रखें तथा दाना डालें, ताकि मूक प्राणियों को राहत मिल सके। कमलेश योगी ने कहा कि अच्छे कर्म करने से अच्छे फल मिलता है और बुरे कर्म का परिणाम भी कई गुना बढ़कर लौटता है। इसलिए हर व्यक्ति को समाज और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि इस सुंदर सृष्टि को बचाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ें।



कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ / स) संभाग-सूरजपुर(छ.ग.)
निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम आमंत्रण)

क्रमांक 387/ एन.आई.टी. -01/2026-27 / व.ले. लि. - दिनांक 25.04.2026

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि :- 08.05.2026 अपराह्न 5.30 बजे तक
ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- 12.05.2026 अपराह्न 5.30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि :- 13.05.2026 पूर्वाह्न 11.30 बजे से

एन.आई.टी. क्र. / निविदा क्र.	कार्य नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में) / अमानत राशि (रु. में) / बैंक साल्वेंसी (रु. में) कार्य पूर्णता हेतु अवधि
01 T0001	जमा मद के तहत जिला जेल सूरजपुर परिसर में पानी टंकी चबुतरा शौचालय सीसी रोड एवं रैप निर्माण कार्य	7.51/5633.00 / 1126500.00 04 माह (वर्षा ऋतु सहित)

नियम व शर्तें :-
ई-पंजीयन के अंतर्गत श्रेणी 'द' से 'अ' में पंजीकृत ठेकेदार निविदा में भाग ले सकेंगे, निविदा प्रपत्र की कीमत 750.00 प्रति निविदा फार्म है, निविदा संबंधी अन्य शर्तें विभागीय वेबसाइट www.cg.mic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभागीय संभागीय कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (म. / स.)
संभाग सूरजपुर

जी नंबर-262700410/3

रायपुर-बिलासपुर पिछड़े, कोरिया बना नंबर-1... क्या बदल गया छत्तीसगढ़ का शिक्षा नक्शा?

जहां फीस कम, वहां नंबर ज्यादा! बोर्ड रिजल्ट ने उलट दी शिक्षा की परिभाषा

- कोरिया टॉप पर... राजधानी नीचे... छत्तीसगढ़ में शिक्षा का बड़ा उलटफेर
- शिक्षा हब फिसले, छोटे जिले चमके... बोर्ड रिजल्ट ने खड़े किए बड़े सवाल...
- नतीजों ने खोली सच्चाई... कोविंग वाले शहर पीछे, सरकारी स्कूल आगे...
- छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट... चौंकाने वाले आंकड़े, शिक्षा मॉडल पर बड़ा सवाल...
- बड़े शहर फेल, छोटे जिले वात : क्या यही है नई शिक्षा कांति?
- कोरिया मॉडल या सिस्टम का खेल? रिजल्ट ने बढ़ाई हलचल
- नंबरों का खेल या मेहनत का फल? बोर्ड रिजल्ट पर उठे गंभीर सवाल
- शिक्षा का सच सामने: ब्रांडेड स्कूल पीछे, सादगी वाली पढ़ाई आगे

-न्यूज डेस्क-

कोरिया/रायपुर, 30 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजों ने इस बार सिर्फ छात्रों के अंक ही नहीं बताए, बल्कि प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड भी खोलकर रख दिया है, 10 वीं और 12 वीं दोनों के परिणाम एक ही दिन घोषित हुए और जैसे ही जिलावार रैंकिंग सामने आई, शिक्षा के पारंपरिक नक्शे पर सवाल लगे कि नई लकीर खिंच गई, जिन जिलों को अब तक 'पिछड़ा' या संसाधनहीन मानकर नजर अंदर किया जाता रहा, वही इस बार टॉप पर नजर आए, जबकि बड़े शहर और कथित शिक्षा हब माने जाने वाले रायपुर और बिलासपुर जैसे जिले रैंकिंग में पीछे खिसक गए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम रहा कोरिया, जिसने 12 वीं में प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर लिया और 10 वीं में भी टॉप-5 में जगह बनाई, यह वही जिला है जहां न बड़े कोविंग संस्थानों की भरमार है, न ही महंगे निजी स्कूलों की चमक-फिर भी परिणाम सबसे बेहतर, दूसरी तरफ, वे शहर जहां अभिभावक लाखों रुपये खर्च कर बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं, वहां का प्रदर्शन औसत से भी नीचे रहा, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर शिक्षा का असली मॉडल कौन सा है? महंगे स्कूल और कोविंग, या फिर अनुशासन और स्कूल आधारित पढ़ाई? इन नतीजों ने न केवल शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर बहस छेड़ दी है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब तक बनाई गई शिक्षा हब की धारणा सिर्फ एक भ्रम थी। क्या छोटे जिलों में वास्तव में पढ़ाई सुधरी है या फिर यह आंकड़ों का कोई अलग ही खेल है? इन सवालों के जवाब भले अभी स्पष्ट न हों, लेकिन इतना तय है कि इस बार का रिजल्ट सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि व्यवस्था पर उठता एक बड़ा सवाल है।

छग बोर्ड रिजल्ट 2026 : 'शिक्षा का सच' या 'नंबरों का खेल' ? छोटे जिलों की उड़ान, बड़े शहरों की गिरावट पर उठे तीखे सवाल

छत्तीसगढ़ में इस साल बोर्ड परीक्षा के परिणामों ने केवल विद्यार्थियों का भविष्य तय नहीं किया, बल्कि पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था का आईना भी सामने रख दिया, 10 वीं और 12 वीं-दोनों कक्षाओं के परिणाम एक ही दिन घोषित हुए और जैसे ही जिलावार आंकड़े सामने आए, एक अजीब-सी जलमांशों के बाद सवालों का शोर शुरू हो गया, यह वही प्रदेश है जहां वर्षों से यह धारणा बनी रही कि बेहतर शिक्षा के लिए बड़े शहरों का रुख करना जरूरी है। अभिभावक अपनी हैसियत से ऊपर जाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए रायपुर और बिलासपुर जैसे शहरों में भेजते रहे। लेकिन इस बार के परिणामों ने इस धारणा को ऐसे झटका दिया है कि अब लोग पूछ रहे हैं- क्या अब तक हम गलत दिशा में भाग रहे थे?

छोटा जिला, बड़ा धमाका कोरिया ने बदली परिभाषा

इस पूरे परिणाम का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला चेहरा बना कोरिया जिला। 12 वीं बोर्ड में प्रदेश में पहला स्थान और 10 वीं में पांचवां स्थान यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह है कि जिस जिले में बड़े-बड़े कोविंग संस्थान नहीं हैं, जहां पढ़ाई का आधार सिर्फ स्कूल है, वहीं से सबसे बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं, न एयर-कंडीशंड क्लासरूम, न लाखों की फीस, न ब्रांडेड स्कूल-फिर भी टॉप, अब सवाल यह उठना लाजमी है कि क्या पढ़ाई सच में किताबों से होती है या फिर फीस की रसीद से?

बस्तर और दूरस्थ जिले : जिन्हें 'कमजोर' कहा गया, वही निकले अग्रवर्ती

10 वीं के परिणाम में बीजापुर और नारायणपुर जैसे जिले शीर्ष पर रहे, कांकेर ने तीसरा स्थान हासिल किया और 12 वीं में भी कांकेर तीसरे स्थान पर बना रहा, यह वही इलाके हैं जिन्हें लंबे समय तक 'पिछड़ा' और 'शिक्षा से दूर' बताया जाता रहा, लेकिन इस बार के परिणामों ने साबित कर दिया कि असली कमजोरी शायद संसाधनों में नहीं, बल्कि सोच में थी, व्यंग्यात्मक सच यह है कि जहां सुविधाएं कम थीं, वहां पढ़ाई ज्यादा हो गई और जहां सुविधाएं ज्यादा थीं, वहां शायद पढ़ाई कहीं खो गई।

शिक्षा हब की हकीकत से चमक ज्यादा, परिणाम कम

अब बात उन जिलों की, जिन्हें शिक्षा का गढ़ माना जाता है, रायपुर राजधानी, बड़े स्कूल, कोविंग का जाल, और हर गली में 'टॉपर्स बनाने' के दावे। लेकिन परिणाम? 10 वीं में 27वां स्थान और 12 वीं में 15वां, बिलासपुर जहां पढ़ाई के नाम पर बड़े-बड़े संस्थान खड़े हैं, वहां 10 वीं में 30वां और 12 वीं में 27वां स्थान, यह वही शहर है जहां 'एडमिशन ओपन' के बोर्ड सालभर लगे रहते हैं और '100% रिजल्ट' के पोस्टर हर दीवार पर चिपके होते हैं, लेकिन असली रिजल्ट आते ही ये दावे शायद छुट्टी पर चले जाते हैं।

दुर्ग-भिलाई : कोविंग का किताब या भ्रम का बुलबुला?

दुर्ग और भिलाई, जो कभी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाने जाते थे, अब निचले पायदान पर दिखाई दे रहे हैं, 10 वीं में दुर्ग 31वें स्थान पर और 12 वीं में 29वें स्थान पर रहा, यह वही क्षेत्र है जहां माता-पिता बच्चों को यह सोचकर भेजते हैं कि यहां से भविष्य संवर जाएगा, लेकिन इस बार के परिणामों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यहां पढ़ाई से ज्यादा 'पैकेजिंग' हो रही है?

एमसीबी: विभाजन का अस्तर या व्यवस्था की विफलता?

कोरिया से अलग होकर बने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक रही, 10 वीं और 12 वीं दोनों में यह जिला अंतिम स्थान पर रहा, एक ही भौगोलिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से निकले दो जिलों के बीच इतना बड़ा अंतर यह बताता है कि शिक्षा केवल संसाधनों का खेल नहीं है, बल्कि प्रबंधन और प्राथमिकता का भी सवाल है, व्यंग्य यह है कि एक ही घर के दो हिस्सों में एक बच्चा टॉप और दूसरा फेल-अब दोहरे किसे दिया जाए?

सरकारी स्कूलों की वापसी से सिस्टम ने ली कटवट या मजबूती बनी मजबूती?

इस बार के परिणामों में सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि सरकारी स्कूलों, खासकर आत्मानंद विद्यालयों का प्रदर्शन बेहतर रहा, जहां पहले सरकारी स्कूलों को 'आखिरी विकल्प' माना जाता था, वही अब वे 'बेहतर विकल्प' बनते नजर आ रहे हैं, यह बदलाव क्या सच में सुधार का संकेत है या फिर निजी स्कूलों की रणनीति में कहीं कमी रह गई? व्यंग्य यही है कि जिन स्कूलों को कभी लोग नजर अंदर करते थे, अब वही स्कूल परिणामों में आगे निकल रहे हैं।

क्या यह सच में सुधार है या सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी?

अब सबसे बड़ा और असहज सवाल क्या यह परिणाम पूरी तरह ईमानदारी से आया है? क्योंकि जिस तरह से अवाक छोटें जिलों का प्रदर्शन इतना बेहतर हुआ और बड़े शहर पीछे चले गए, उसने कई लोगों के मन में संदेह भी पैदा किया है, क्या मूल्यांकन में कोई बदलाव हुआ? क्या रिजल्ट को बेहतर दिखाने के लिए कोई 'प्रबंधन' किया गया? या फिर यह वास्तव में शिक्षा व्यवस्था के सुधार का परिणाम है? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास साफ नहीं है, लेकिन यह तय है कि पारदर्शिता की मांग अब और तेज होगी।

छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2026 छोटे जिलों का कमाल, शिक्षा हब फेल!

कोरिया 12 वीं में नंबर-1, 10 वीं में 5 वें स्थान पर

10 वीं बोर्ड परिणाम 2026			12 वीं बोर्ड परिणाम 2026		
रैंक	जिला	प्रतिशत	रैंक	जिला	प्रतिशत
1	बीजापुर	96.06%	1	कोरिया	95.64%
2	नारायणपुर	94.80%	2	बीजापुर	95.03%
3	कांकेर	93.68%	3	कांकेर	93.75%
4	जसपुर	93.29%	4	रायपुर	93.32%
5	कोरिया	93.02%	5	गवियाबंद	92.89%
...
27	रायपुर	71.05%	15	रायपुर	84.79%
30	बिलासपुर	65.30%	27	बिलासपुर	79.19%
33	एमसीबी	59.12%	33	एमसीबी	62.40%

नतीजों ने उठाए बड़े सवाल

- क्या बड़ों छोटे जिलों की शिक्षा का सिस्टम?
- क्या बड़े शहरों में फीस कटने का खेल?
- क्या रिजल्ट पूरी तरह पारदर्शी है?

छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2026: 10 वीं बनाम 12 वीं (सुवनात्मक चार्ट)

जिला	10 वीं रैंक	10 वीं %	12 वीं रैंक	12 वीं %	प्रदर्शन विवरण
कोरिया	5	93.02	1	95.64	12 वीं में नंबर-1 का उछाल
बीजापुर	1	96.06	2	95.03	दोनों में लगातार टॉप
कांकेर	3	93.68	3	93.75	स्थिर उच्च प्रदर्शन
जसपुर	4	93.29	4	93.32	संतुलित रिजल्ट
नारायणपुर	2	94.80	12	86.92	12 वीं में गिरावट
रायपुर	27	71.05	15	84.79	12 वीं में सुधार, पर कमजोर निष्पत्ति
बिलासपुर	30	65.30	27	79.19	दोनों में कमजोर प्रदर्शन
दुर्ग	31	63.12	29	77.91	शिक्षा हब, लेकिन निचले स्तर पर
भरतपुर	16	83.09	24	80.56	गिरावट
मुरादापुर	17	82.75	13	86.46	सुधार दिखा
रायगढ़	18	80.06	19	83.45	सुधार प्रदर्शन
महासमुंद्र	19	79.35	22	80.89	सुधारी गिरावट
कोटा	22	77.58	18	83.48	सुधार
धमरगढ़ी	23	76.18	17	84.18	अच्छा सुधार
बागोद	29	65.94	30	77.79	कमजोरी
बन्नी	28	68.78	31	72.07	लगातार गिरावट
ताजमहीर-बाघा	32	59.90	32	65.73	निचले स्तर पर फिल
MCB	33	59.12	33	62.40	सबसे कमजोर जिला

मुख्य निष्कर्ष (चार्ट से निकलते बड़े टैंड)

- छोटे जिले = बेहतर प्रदर्शन**
 - कोरिया, बीजापुर, कांकेर जैसे जिले टॉप पर
 - संसाधन कम, लेकिन परिणाम मजबूत
- बड़े शहर = अपेक्षाकृत कमजोर**
 - रायपुर और बिलासपुर दोनों नीचे
 - 'शिक्षा हब' की छवि पर सवाल
- 10 वीं से 12 वीं में बड़ा बदलाव**
 - कई जिलों में भारी उतार-चढ़ाव
 - उदाहरण: नारायणपुर (2-12), कोरिया (5-1)
- सबसे चिंतनस्पष्ट**
 - मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला लगातार अंतिम स्थान

सरल निष्कर्ष

- 'जहां सिस्टम मजबूत, वहां रिजल्ट मजबूत'
- 'जहां ब्रांड बड़ा, वहां जरूरी नहीं कि परिणाम भी बड़ा हो।'

सूरजपुर जिले का छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित

12 वीं में 86.46 प्रतिशत व 10 वीं में 82.75 प्रतिशत विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण

बेटियों ने एक बार फिर मारी बाजी, बालकों से आगे रही बालिकाएं

पिछले वर्ष की तुलना में 12 वीं के परिणाम में 14 प्रतिशत व 10 वीं में 11 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि

-संवाददाता- सूरजपुर, 30 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा घोषित हुई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 के परिणामों में सूरजपुर जिले के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिले का 12 वीं का कुल परीक्षाफल 86.46 प्रतिशत तथा 10 वीं का परीक्षाफल 82.75 प्रतिशत रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में 12 वीं के परिणाम में लगभग 14 प्रतिशत एवं 10 वीं के परिणाम में लगभग 11 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो जिले की शैक्षणिक प्रगति का प्रमाण है।

12 वीं के परीक्षा परिणाम का विवरण- हायर सेकेण्डरी परीक्षा 2026 में सूरजपुर जिले से कुल 8158 विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें 3491 बालक एवं 4667 बालिकाएं शामिल थीं।

परीक्षा में 8081 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए तथा 8067 का परिणाम घोषित किया गया, इनमें से कुल 6975 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनमें 2863 बालक एवं 4112 बालिकाएं हैं। प्रथम श्रेणी में 4147, द्वितीय श्रेणी में 2724 तथा तृतीय श्रेणी में 103 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 83.22 तथा बालिकाओं का प्रतिशत 88.86 रहा, जो दर्शाता है कि बेटियों ने इस वर्ष भी बालकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।

सकायवार प्रदर्शन में विज्ञान अग्रवर्ती-संकायवार



परिणामों पर दृष्टि डालें तो विज्ञान संकाय में सर्वाधिक 91.63 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें बालिकाओं का प्रतिशत 94.24 रहा। इसके पश्चात वाणिज्य संकाय में 89.57 प्रतिशत, गृह विज्ञान में 86.66 प्रतिशत, कला संकाय में 81.61 प्रतिशत तथा कृषि संकाय में 73.91 प्रतिशत परिणाम रहा। ललित कला संकाय में पंजीकृत विद्यार्थी अनुपस्थित रहे।

10 वीं के परीक्षा परिणाम का विवरण- हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 में सूरजपुर जिले से कुल 10170 विद्यार्थी पंजीकृत हुए, जिनमें 4547 बालक एवं 5623 बालिकाएं थीं, परीक्षा में 10002 विद्यार्थी सम्मिलित हुए तथा 9938 का परिणाम घोषित हुआ। कुल 8224 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनमें 3478 बालक एवं 4746 बालिकाएं शामिल हैं, प्रथम श्रेणी में 4466, द्वितीय श्रेणी में 3560 तथा तृतीय श्रेणी में 198 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 79.22 एवं बालिकाओं का प्रतिशत 85.54 रहा है। यहां भी बालिकाओं ने बालकों से

बेहतर प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परचम उलटारा है।

बेटियों ने बढ़ाया जिले का मान...

दोनों ही परीक्षाओं में बालिकाओं ने बालकों की तुलना में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, 12 वीं में जहां बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों से लगभग साढ़े पांच प्रतिशत अधिक रहा, वहीं 10 वीं में यह अंतर लगभग सवा छह प्रतिशत का है, यह आंकड़े जिले में बेटियों की शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता और उनकी मेहनत का जीवंत प्रमाण है।

जिला प्रशासन ने दी बधाई...

जिला प्रशासन सूरजपुर ने सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को बधाई देते हुए उनके उज्वल भविष्य की कामना की है, साथ ही उन विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित किया गया है जो अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सके, प्रशासन ने ऐसे विद्यार्थियों से निराश न होकर पुनः मेहनत के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है।

सुप्रीम कोर्ट में 'केविएट' दायर करेगा छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, शिक्षकों से नहीं लिया जाएगा कोई आर्थिक सहयोग

शिक्षकों के हित में बड़ा निर्णय, सुप्रीम कोर्ट में केविएट की तैयारी...

-संवाददाता- कोरिया/सूरजपुर, 30 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने शिक्षकों के पेंशन अधिकारों की रक्षा को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित प्रांतीय वचुंअल बैठक में यह निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पेंशन के संबंध में दिए गए फैसले को सुरक्षित रखने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में केविएट याचिका दायर की जाएगी, एसोसिएशन का मानना है कि यह कदम इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से एकतरफा आदेश लेकर उच्च न्यायालय के फैसले को प्रभावित न किया जा सके।

आर्थिक सहयोग नहीं लिया जाएगा, एसोसिएशन उदात्तता पूरा खर्च

बैठक में यह स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया कि केविएट दायर करने के लिए किसी भी शिक्षकों से कोई आर्थिक सहयोग या चंदा नहीं लिया जाएगा, एसोसिएशन ने साफ किया कि इस पूरी प्रक्रिया का खर्च संगठन स्वयं वहन करेगा, इसके साथ ही शिक्षकों को आगाह किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति या समूह केविएट के नाम पर राशि मांगता है, तो उससे सतर्क रहें।

शिक्षकों को जागरूक करने का अभियान, 'क्यूआर कोड' से सावधान रहने की अपील

वचुंअल बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिले में बैठक आयोजित कर शिक्षकों को जागरूक किया जाएगा, विशेष रूप से यह अपील की गई कि किसी भी भ्रामक सूचना या बहकावे में न आए, केविएट या पेंशन के नाम पर मांगी जा रही राशि से सावधान रहें, क्यूआर कोड के माध्यम से होने वाले संभावित फर्जी कलेक्शन से दूरी बनाए रखें।

हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत, संघर्ष जारी रखने का संकल्प-बैठक में



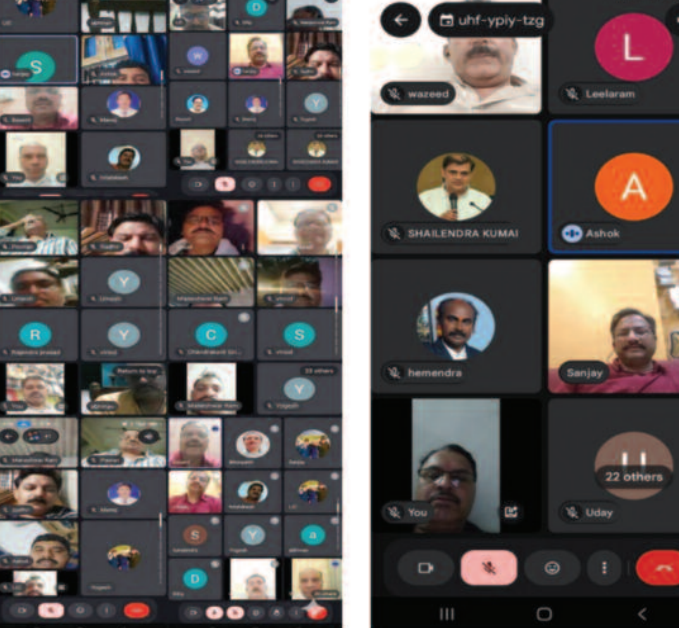
23 जनवरी 2026 और 17 फरवरी 2026 को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिए गए फैसलों का स्वागत किया गया, सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि यह फैसला शिक्षकों के लंबे संघर्ष की जीत है और हम इस लड़ाई को अंतिम छोर तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, एसोसिएशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार को बिना पक्ष सुने कोई स्थगन (स्टे) आदेश प्राप्त न हो सके।

पेंशन को बताया अधिकार, नहीं 'खैरात'

बैठक में न्यायालय के फैसले की प्रमुख बातों पर भी विस्तार से चर्चा की गई, इस दौरान यह बताया गया कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत पेंशन एक अधिकार है, न कि 'खैरात' या 'गुणकारी'। प्राशासनिक नियंत्रण को ध्यान में रखना आवश्यक है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता और अवसर के सिद्धांतों का पालन जरूरी है, पेंशन कोई दया या खैरात नहीं, बल्कि कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है।

संवैधानिक प्रावधानों को जोड़ने की मांग, सरकार से जारी रहेगा संवाद

टीचर्स एसोसिएशन ने यह भी स्पष्ट किया कि संगठन स्तर पर सरकार से लगातार संवाद



कर संवैधानिक प्रावधानों के तहत पेंशन एक अधिकार है, न कि 'खैरात' या 'गुणकारी'। प्राशासनिक नियंत्रण को ध्यान में रखना आवश्यक है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता और अवसर के सिद्धांतों का पालन जरूरी है, पेंशन कोई दया या खैरात नहीं, बल्कि कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है।

कर संवैधानिक प्रावधानों के तहत पेंशन एक अधिकार है, न कि 'खैरात' या 'गुणकारी'। प्राशासनिक नियंत्रण को ध्यान में रखना आवश्यक है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता और अवसर के सिद्धांतों का पालन जरूरी है, पेंशन कोई दया या खैरात नहीं, बल्कि कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है।

बसदेई पीएचसी में आरएमए का कब्जा... 10 महीने बाद भी एमबीबीएस डॉक्टर बेप्रभार

नियमों को टेंगा बसदेई स्वास्थ्य केंद्र में आरएमए चला रहा व्यवस्था...डॉक्टर हाशिये पर...

- अंगद के पांव बना आरएमए का दबदबा, एमबीबीएस डॉक्टर को नहीं मिली जिम्मेदारी
- स्वास्थ्य केंद्र या निजी तंत्र? बसदेई में आरएमए का राज, सिस्टम बेबस
- 10 साल से एक ही प्रभारी, बदलते रहे अधिकारी पर नहीं बदली व्यवस्था
- मरीज परेशान, डॉक्टर बेप्रभार... बसदेई स्वास्थ्य केंद्र पर उठे बड़े सवाल
- जीवनदीप फंड से लेकर कुर्सी खरीद तक चर्चा, बसदेई पीएचसी विवादों में...
- क्या अधिकारियों के आगे सिस्टम हुआ नतमस्तक? बसदेई पीएचसी में गहराया विवाद

-समवेत खान-

सूरजपुर, 30 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले के बसदेई स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों गंभीर विवाद और सवालियों के केंद्र में है, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, जिनमें सबसे प्रमुख मुद्दा प्रभार को लेकर बना हुआ है। जानकारी के अनुसार, केंद्र में पदस्थ एक एमबीबीएस डॉक्टर को ज्वान किए लगभग 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें स्वास्थ्य केंद्र का प्रभार नहीं सौंपा गया है, दूसरी ओर, वर्षों से एक आरएमए (रूरल मेडिकल असिस्टेंट) नियमों के विपरीत प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा है और उसका प्रभाव इतना मजबूत बताया जा रहा है कि स्थिति 'अंगद के पांव' जैसी बन गई है, जहाँ बदलाव की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही।

निरीक्षण या 'चाय-नाश्ता देर'? बसदेई स्वास्थ्य केंद्र में अफसरों की भूमिका पर सवाल

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसदेई में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं और शिकायतों के बीच अब एक और गंभीर पहलू चर्चा में है कि अधिकारियों के निरीक्षण का तरीका स्थानीय स्तर पर यह आरोप लग रहा है कि जब भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और खंड चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करते हैं, तो उनकी जानकारी पहले से ही प्रभारी तक पहुंचा दी जाती है, ग्रामीणों और सूत्रों के मुताबिक, निरीक्षण से पहले ही स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी को यह संदेश पहुंच जाता है कि 'चाय-नाश्ता तैयार रखना।' ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह निरीक्षण वास्तव में व्यवस्था सुधारने के लिए होता है या फिर केवल औपचारिकता निभाने तक सीमित रह जाता है, यदि शिकायतें लगातार मिल रही हैं, चाहे वह प्रभार को लेकर हो, मरीजों की परेशानियों हो या कार्यप्रणाली में गड़बड़ी तो अपेक्षा की जाती है कि अधिकारी बिना सूचना के औचक निरीक्षण करें, लेकिन यदि निरीक्षण पहले से तय और सूचित हो, तो वास्तविक स्थिति सामने आ ही

10 साल से एक ही प्रभारी, नहीं बदली तस्वीर-

बसदेई स्वास्थ्य केंद्र में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है, बताया जा रहा है कि पिछले लगभग 10 वर्षों से एक ही व्यक्ति प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा है, इस दौरान कई बार सीएमएचओ बदले, कई डॉक्टरों की पदस्थापना हुई, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की कार्यप्रणाली में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला, लंबे समय तक एक ही व्यक्ति के प्रभारी रहने से न केवल पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, बल्कि यह भी आशंका पैदा होती है कि कहीं व्यवस्था पर व्यक्तिगत नियंत्रण तो नहीं बन गया है।

एमबीबीएस डॉक्टर को जिम्मेदारी से दूर रखने पर सवाल-

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब केंद्र में एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद हैं, तो उन्हें प्रभार क्यों नहीं दिया जा रहा, क्या यह केवल प्रशासनिक लापरवाही है या इसके पीछे कोई और कारण है? सूत्रों की मानें तो इस स्थिति के कारण स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में असंतुलन की स्थिति बन गई है। योग्य डॉक्टर होने के बावजूद उन्हें निर्णय लेने और व्यवस्था सुधारने का अवसर नहीं मिल रहा।

नहीं सकती, इस तरह के 'पूर्व सूचना वाले निरीक्षण' में अक्सर वही दिखाया जाता है जो दिखाना होता है, व्यवस्थाएं अस्थायी रूप से ठीक कर दी जाती हैं, स्टाफ मौजूद दिखाता है और कागजों में सब कुछ व्यवस्थित नजर आता है, लेकिन जैसे ही अधिकारी लौटते हैं, स्थिति फिर पहले जैसी हो जाती है, यही कारण है कि अब क्षेत्र के लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि अधिकारियों की जिम्मेदारी आखिर क्या है सिर्फ औपचारिक दौर कर चाय-नाश्ता करना या फिर स्वास्थ्य केंद्र की वास्तविक स्थिति सुधारना? विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी मानना है कि यदि किसी संस्था में लगातार शिकायतें मिल रही हैं, तो वहाँ औचक निरीक्षण ही सबसे प्रभावी तरीका होता है। इससे न केवल वास्तविक स्थिति सामने आती है, बल्कि जिम्मेदार कर्मचारियों में जवाबदेही का भाव भी विकसित होता है, बसदेई स्वास्थ्य केंद्र का मामला यह संकेत देता है कि निरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और गंभीरता की कमी है, यदि यही स्थिति बनी रही, तो शिकायतें केवल कागजों तक सीमित रह जाएंगी और जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं होगा।

नियमों के विपरीत व्यवस्था, जिम्मेदार मौन

स्वास्थ्य विभाग के सामान्य नियमों के अनुसार, जहाँ एमबीबीएस डॉक्टर पदस्थ हों, वहाँ प्रभार

उन्हें दिया जाना चाहिए, लेकिन बसदेई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में यह नियम लागू होता नहीं दिख रहा, स्थानीय लोगों और सूत्रों का कहना है कि आरएमए का दबदबा इतना अधिक है कि जिम्मेदार अधिकारी भी इस व्यवस्था को बदलने में असमर्थ या अनिच्छुक नजर आ रहे हैं, इस स्थिति ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि यदि अधिकारी चाहें तो यह व्यवस्था तुरंत बदली जा सकती है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

जीवनदीप समिति और खर्च पर उठे सवाल

मामला केवल प्रभार तक सीमित नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, स्थानीय स्तर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जीवनदीप समिति के पैसों में गड़बड़ी और बंदरबांट हो रही है, इसके अलावा, 40,000 रुपये की कुर्सी खरीदे जाने की चर्चा भी क्षेत्र में जोरों पर है, हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन चर्चाओं ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है, लोग मांग कर रहे हैं कि इन सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए।

बसदेई स्वास्थ्य केंद्र में RMA का दबदबा! 10 महीने बाद भी MBBS डॉक्टर को नहीं मिला प्रभार!

क्या आखिर RMA प्रभारी के आगे जिम्मेदार हैं नतमस्तक?



आखिर जिम्मेदार अधिकारी कब लेंगे संज्ञान?

10 महीने से खाली पड़ा है MBBS डॉक्टर का पद। RMA प्रभारी का हावी है दबदबा! स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा सीधा असर। जिम्मेदार अधिकारी कब लेंगे संज्ञान?

समय पर नहीं पहुंचते प्रभारी, मरीज परेशान

बसदेई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को होने वाली परेशानियां भी इस पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं, ग्रामीणों का आरोप है कि प्रभारी समय पर अस्पताल नहीं पहुंचते, जिससे दूर-दराज से आने वाले मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, सुबह से ही मरीज इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर की अनुपस्थिति या देरी के कारण उपचार शुरू नहीं हो पाता, कई बार गंभीर मरीजों को मजबूरी में निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता है।

ग्रामीणों में बढ़ता आक्रोश

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति में उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है, लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि एमबीबीएस डॉक्टर को तुरंत प्रभार सौंपा जाए, वर्तमान व्यवस्था की जांच की जाए, मरीजों को समय पर उपचार सुनिश्चित किया जाए।

जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल

इस मामले में सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, बीएमओ और सीएमएचओ स्तर पर कार्रवाई का अभाव यह संकेत देता है कि या तो मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है, यह चुप्पी कई तरह की आशंकाओं को जन्म देती है और प्रशासन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है।

व्यवस्था सुधार की जरूरत

बसदेई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति यह दर्शाती है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में अभी भी कई स्तरों पर सुधार की जरूरत है, यदि समय रहते इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो स्थिति और बिगड़ सकती है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा।

सवाल सिर्फ प्रभार का नहीं, पूरी व्यवस्था का...

बसदेई स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला केवल प्रभार को लेकर विवाद नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है, जब योग्य डॉक्टर होने के बावजूद उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जाती और नियमों की अनदेखी की जाती है, तो यह व्यवस्था पर अविश्वास पैदा करता है, अब यह देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या वास्तव में बसदेई स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति में सुधार होता है या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाता है।

पेट्रोल, डीजल के अवैध बिक्री पर प्रशासन की सख्ती...

निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की जा रही सतत निगरानी



-संवाददाता-

बलरामपुर, 30 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

जिले में पेट्रोल की आपूर्ति को लेकर प्रशासन द्वारा पेट्रोल पंपों की स्थिति की निगरानी तेज कर दी गई है। इस संबंध में खाद्य विभाग, पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि पेट्रोल की आपूर्ति में आई अस्थायी बाधा को दूर करने के लिए संबंधित तेल कंपनियों से समन्वय स्थापित किया गया है और जिले के सभी पंप पर नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही सभी पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित दर पर ही पेट्रोल की बिक्री करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि बोललों में अवैध रूप से पेट्रोल बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अवैध बिक्री की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि सख्त कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि संभावित आपूर्ति व्यवधानों की आशंकाओं के दृष्टिगत इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ईंधन आपूर्ति से संबंधित किसी भी समस्या, शिकायत या जानकारी के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष नंबर 92026-08795 पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे नागरिक सीधे अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। उन्होंने कहा कि जिले में पारदर्शिता और सुचारु व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

संगठनात्मक मजबूती पर केंद्रित बैठक... अटल कुंज में भाजयुमो की परिचयात्मक बैठक संपन्न, युवाओं में जोश भरते नजर आए प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा



-संवाददाता-

सूरजपुर, 30 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।

भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) जिला सूरजपुर की एक महत्वपूर्ण परिचयात्मक बैठक जिला भाजपा कार्यालय 'अटल कुंज' में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा उपस्थित रहे, बैठक का मुख्य उद्देश्य नवनियुक्त पदाधिकारियों का परिचय कराना तथा संगठन की आगामी कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा करना था, कार्यक्रम में जिले के विभिन्न मंडलों से आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने इसे और अधिक प्रभावी बना दिया। बता दें की अटल कुंज में आयोजित यह बैठक न केवल परिचयात्मक रही, बल्कि संगठनात्मक ऊर्जा और दिशा देने वाली भी साबित हुई, प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में युवा कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया, जिससे आने वाले समय में भाजपा और भाजयुमो की गतिविधियों में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

मंच पर उपस्थित प्रमुख नेता-कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली

स्वागत उद्घोषण में कल युवा शक्ति पर विश्वास-

कार्यक्रम की शुरुआत भाजयुमो जिलाध्यक्ष देव गुप्ता के स्वागत उद्घोषण से हुई, उन्होंने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं मालाओं से स्वागत करते हुए कहा कि सूरजपुर जिले का युवा कार्यकर्ता ऊर्जा, उत्साह और समर्पण से भरा हुआ है, उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में संगठन नई ऊंचाइयों को छुएगा।

जिलाध्यक्ष भाजपा का मार्गदर्शन-

भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी ने अपने संबोधन में कहा कि युवा मोर्चा संगठन की अग्रिम पंक्ति की शक्ति है, उन्होंने कार्यकर्ताओं को अनुशासन, निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का संदेश दिया, साथ ही उन्होंने संगठन की मजबूती और जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया।

मनोहर सोनी, आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संगठनात्मक रितेश गुप्ता, भाजपा महामंत्री शशिकांत गर्ग, उपाध्यक्ष संत सिंह, कोषाध्यक्ष संदीप अग्रवाल, जनपद अध्यक्ष स्वाति सिंह, नगरपालिका उपाध्यक्ष शैलेश अग्रवाल, जिला मंत्री राजेश्वर तिवारी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष देव गुप्ता, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष नूतन विश्वास, प्रदेश पदाधिकारी विभूति कश्यप, रवीन्द्र भारती, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मुकेश साह एवं अंकुश सिंह, सह कार्यालय मंत्री भाजपा संजु सोनी सहित अन्य पदाधिकारी मंच पर उपस्थित रहे।

संगठनिक विचार और प्रेरणा-भाजपा महामंत्री शशिकांत गर्ग ने



बल्कि परिवर्तन का वाहक है। हमें एकजुट होकर जन-सरोकार के मुद्दों को उठाना है और संगठन को मजबूत बनाना है, उन्होंने सूरजपुर जिले के युवाओं के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले समय में यहाँ का संगठन एक मिसाल कायम करेगा।

बैठक का उद्देश्य और भविष्य की रणनीति-इस परिचयात्मक बैठक का मुख्य उद्देश्य नवनियुक्त पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करना था, बैठक में संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक सक्रियता, और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई, कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया गया कि वे संगठन की नीतियों और कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

संचालन और आभार प्रदर्शन

कार्यक्रम का संचालन भाजयुमो महामंत्री रूपेंद्र कुशवाहा एवं उपाध्यक्ष पप्पू साह द्वारा किया गया। अंत में अतिथियों और उपस्थित कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया, इस अवसर पर जिले के सभी मंडलों से आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं की सक्रिय उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल और प्रभावी बनाया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र... शासकीय संकल्प को लेकर पक्ष-विपक्ष में जोरदार बहस

33% महिला आरक्षण लागू करने शासकीय संकल्प होगा पेश, सदन में महिलाओं की संख्या पर हुई बहस

सीएन साय ने पेश किया महिला आरक्षण बिल पर चर्चा का प्रस्ताव, विपक्ष ने गुमराह करने का लगाया आरोप...

रायपुर, 30 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र में महिला सशक्तिकरण को लेकर शासकीय संकल्प पेश किया जाएगा। इसमें परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू करने की मांग की गई है। इस विशेष सत्र में प्रदेश भर की 500 से ज्यादा महिला जनप्रतिनिधि शामिल हुई हैं। सत्र की शुरुआत दोनों पक्षों में तीखी बहस के साथ हुई। विपक्ष ने कहा कि सदन के बाहर निंदा प्रस्ताव की बात कही गई थी, अब शासकीय संकल्प लाकर चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है जनगणना के बाद महिला आरक्षण लागू किया जाए। चर्चा के बीच कांग्रेस विधायक अनिला भेंडिया ने कहा कि आरक्षण बिल चुनावी झुनझुना है, हमारे देश की महिलाएं जानती हैं कि 2023 में बिल पास हुआ पर उसे लागू नहीं किया गया, महिलाओं को अपने अधिकार मालूम हैं। सत्ता पक्ष से डिटी सीएम साव ने तंज करते हुए कहा कि, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 500 रुपए देने का वादा किया था, आज किस मुंह से ये महिला के अधिकारों की बात कर रहे हैं। इस दौरान महिलाओं की संख्या को लेकर भी सदन में बहस हुई। विपक्ष ने कहा कांग्रेस ने महिलाओं को सबसे ज्यादा अवसर दिया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा से 54 में 8, कांग्रेस से 35 में 11 महिला विधायक हैं।



किरण सिंहदेव बोले... बिल को ध्वस्त करने का काम कांग्रेस ने किया

महिला आरक्षण पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा...आजादी के बाद से 5 दशक तक देश में कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान महिलाओं के लिए काम क्यों नहीं किया? बीजेपी ने संसद में बिल लाया तब समर्थन क्यों नहीं दिया। संसद में बिल को ध्वस्त करने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहता है।

अजय चंद्रकार- हमारी सरकार ने महिलाओं को संख्याओं में 50 फीसदी आरक्षण दिया

महिला आरक्षण पर चर्चा में बोले विधायक अजय चंद्रकार-अहम संकल्प पर चर्चा हो रही, अपने तरीके से अपना पक्ष रखा। महिला की स्थिति पर कांग्रेस ने कभी नहीं चर्चा नहीं की। अंबेडकर के साथ कैसा व्यवहार कांग्रेस ने किया, सब जानते हैं, देश का ऐसा दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़ जहां हमारी सरकार ने आरक्षण दिया, जहां महिलाओं को संख्याओं में 50 फीसदी आरक्षण दिया।

किया है। लोकतंत्र में कांग्रेस ने देश की महिलाओं को पहली पंक्ति में रखा। कांग्रेस ने पहली महिला प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। बीजेपी की मेन शाखा क्रस है, जहां महिलाएं ही वर्जित हैं। बीजेपी महिलाओं की

विरोधी है। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे करने का काम किया है। यह कार्रवाई शराब घोटाले के फरार आरोपी विकास अग्रवाल के सिंडिकेट से जुड़े तार खंगालने के लिए की जा रही है, जो अनवर डेवर का करीबी और विवेक अग्रवाल का भाई बताया जा रहा है।

किस मुंह से महिला अधिकारों की बात कर रही कांग्रेस : डिटी सीएम

डिटी सीएम साव ने कांग्रेस विधायक अनिला भेंडिया के वक्तव्य के दौरान तंज करते हुए कहा कि हमारी 3 बहनों एक साथ खड़े होकर बोल रही थी, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 500 रुपये देने का वादा किया था, आज किस मुंह से ये महिला के अधिकारों की बात कर रहे हैं।

अनिला भेंडिया बोली- 543 सीटों पर 33% आरक्षण देने बीजेपी की हिम्मत नहीं

विपक्ष से पूर्व मंत्री अनिला भेंडिया ने चर्चा में कहा... कांग्रेस 33% महिला आरक्षण के पक्ष में है। वर्तमान सीटों पर ही 33% आरक्षण लागू किया जाए। बीजेपी की हिम्मत 543 सीटों पर 33% आरक्षण देने की नहीं है। महिलाएं इसका बदला बीजेपी से जरूर लेंगी। अनिला भेंडिया ने कहा... बीजेपी महिलाओं की कंधों पर बंदूक रखकर उनका अपमान कर रही है। चुनाव के बीच सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी। महिला सुरक्षा पर सरकार बात करती है, आज कौन सी महिला देश में सुरक्षित है यह बताएं? देश में संस्कृति हमेशा नारी सम्मान की बात करती है।

महिला आरक्षण बिल के बीच गैस सिलेंडर को लेकर बहस

उज्ज्वला योजना पर चर्चा के बीच कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने कहा... आज हर घर में चूल्हा जल रहा है। सरकार ने 500 में सिलेंडर देने की बात कही थी। सत्ता के पक्ष के विधायकों ने कहा- ईरान में युद्ध चल रहा, इसलिए संकट है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष से कहा- आप लोग नहीं चाहते महिला आरक्षण पर चर्चा हो इसलिए बीच-बीच में बोल रहे।

कवासी लखमा- 2022 में बीजेपी ने जनगणना क्यों नहीं कराया?

विधायक कवासी लखमा ने कहा 2011 में कांग्रेस ने जनगणना की थी। साल 2022 में बीजेपी सरकार को करना था, क्यों नहीं किया गया? इस पर डिटी सीएम अणु साव ने कहा कांग्रेस ने सिर्फ महिलाओं के साथ छल किया है।

सभापति तालिका में 2 महिला विधायकों के नाम शामिल : इस विशेष सत्र के दौरान महिलाओं के सम्मान में विधानसभा में एक फैसला लिया गया। 2 महिला विधायकों को सभापति तालिका में शामिल किया गया है। पक्ष की ओर से लता उर्सेडी और विपक्ष की ओर से अनिला भेंडिया सभापति तालिका में शामिल हुईं हैं। नियम 9 एक को शिथिल करते नाम निर्देशित किया गया।

संगिता सिन्हा बोली... महिलाएं समझदार हैं... बहकाव दे मत

कांग्रेस विधायक संगिता सिन्हा ने कहा... जब पूरे देश में चुनाव आने वाला है, तो मोदी जी अचानक से घोषणा करते हैं कि 33% आरक्षण लाया जाएगा। महिलाएं समझदार हैं, आप बहकाने का प्रयास मत कीजिए। आप सबसे पहले जनगणना करवाइए, इसके बाद महिला आरक्षण बिल लागू करें। चुनाव हारने का डर था, इसलिए ये बिल लाए हैं।

कांग्रेस बोली... हमने सबसे ज्यादा महिलाओं को अवसर दिया

विपक्ष के विधायकों ने कहा... कांग्रेस ने महिलाओं को सबसे ज्यादा अवसर दिया। छत्तीसगढ़ में भाजपा से 54 में 8, कांग्रेस से 35 में 11 महिला विधायक हैं। कांग्रेस ने वास्तव में महिलाओं को अवसर प्रदान किया, इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष की महिलाओं के बीच तीखी बहस हुई।

कांग्रेस बोली... बच्ची टेप टेप हुआ, तब सरकार ने क्या टेप लगा लिया था?

अनिला भेंडिया ने कहा मणिपुर जल रहा था तो ये लोग कहा थे, उन्नाव की महिला सड़क पर घूम रही थी तो पीएम ने मुंह पर टेप लगा लिया था। प्रदेश में 3 साल की बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ सीएम ने क्या टेप लगा लिया था। किस मुंह से आप महिला अधिकार की बात कर रहे हैं।

एमएलए रामकुमार बोले... बीजेपी महिलाओं की विरोधी है...

कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने कहा... कांग्रेस ने हमेशा से महिलाओं का सम्मान

रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों के लिए राहत... 14 मई तक करें पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन

रायपुर, 30 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से छात्रों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित होने के बाद पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका की छत्रा प्रति देखने का मौका दिया है। जो विद्यार्थी अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे अब अपने परिणाम की दोबारा जांच करवा सकते हैं। मंडल के अनुसार, छत्र 14 मई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि 29 अप्रैल 2026 को रिजल्ट जारी होने के बाद केवल 15 दिनों की समय सीमा के भीतर ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तय तारीख के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन मान्य नहीं होगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रक्रिया पूरी करें, ताकि तकनीकी या अन्य किसी परेशानी से बचा जा सके। यह अवसर उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिन्हें अपने प्राप्त अंकों में सुधार की उम्मीद है।



पत्नी की हत्या के बाद 'करंट' से मौत दिखाने की खौफनाक चाल नाकाम, आरोपी पति गिरफ्तार

जाजगीर, 30 अप्रैल 2026। जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अश्लील संबंध के चलते अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसे हादसा दिखाने के लिए खतरनाक साजिश रच डाली। घटना बलौदा थाना क्षेत्र की है, जहां आरोपी महेंद्र कुमार मिरी ने 28-29 अप्रैल की रात अपनी पत्नी ललितता मिरी का गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने सख्त छिपाने के लिए बाथरूम में पानी से भरी बाल्टी में इमर्शन रॉड चालू कर शव को उसके पास रख दिया, ताकि मामला करंट लगने से मौत जैसा लगे। बताया जा रहा है कि आरोपी का किसी अन्य महिला से संबंध था, जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। घटना वाली रात भी इसी बात पर झगड़ा हुआ, जो इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में पत्नी की जान ले ली। इसके बाद उसने बड़ी चालाकी से पूरी घटना को हादसा साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह योजना ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरुआती पड़ताल में आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन कड़ी पड़ताल के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की आगे की जांच जारी है।



माइनिंग में 100% डिजिटल कंट्रोल खदानों की ड्रोन से जांच, अवैध खनन पर छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी चोट

रायपुर, 30 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ में खनिज ऑनलाइन 2.0 लागू हो गया है। इसके बाद रेत खदानों की ई-टेंडरिंग, टिन की कीमत 4 गुना बढ़ी। अवैध माइनिंग वालों पर अब सरकार की ऑनलाइन नजर रहेगी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने खनिज कारोबार को पारदर्शी बनाने और राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा डिजिटल बदलाव किया है। 'खनिज ऑनलाइन 2.0' पोर्टल लागू होने के बाद अब खदान संचालकों को रेंटल्टी पर्ची के लिए दफ्तरी के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ई-रेंटल्टी और ई-ट्रांजिक्ट पास की सुविधा 24 घंटे ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। इससे न केवल समय और लागत बचेगी, बल्कि सिरस्टम में मानवीय हस्तक्षेप कम होने से गड़बड़ियां पर भी अंकुश लगेगा। नई व्यवस्था के तहत खदानों की रिजल्ट डेटा माॉनिटरिंग संभव हो गई है। खनिज अधिकारियों का दावा है कि इससे अवैध खनन, ओवरलोडिंग और बिना परमिट खनिज परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता-कारोबारी के ठिकानों पर ईडी रेड दुर्ग में चतुर्भुज राठी के घर-दफ्तर में छापेमारी, बिलासपुर में विवेक अग्रवाल के यहां दबिशा

दुर्ग-भिलाई, 30 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने दुर्ग और बिलासपुर में रेड मारी है। दुर्ग में 'अमर इन्फ्रा' के संचालक और भाजपा नेता चतुर्भुज राठी के निवास और दफ्तर पर दबिशा दी गई है, जहां टीम उनके आधा दर्जन फर्मों के वित्तीय दस्तावेजों और निवेश के रिकॉर्ड खंगाल रही है। भिलाई में गोविंद मंडल के घर फेक्ट्री में भी जांच जारी है। दूसरी ओर, बिलासपुर में बड़े सर्राफा कारोबारी विवेक अग्रवाल के घर और सदर बाजार स्थित 'श्री राम ज्वेलर्स' पर ईडी के 10 से ज्यादा अधिकारियों ने छापेमारी है। यह कार्रवाई शराब घोटाले के फरार आरोपी विकास अग्रवाल के सिंडिकेट से जुड़े तार खंगालने के लिए की जा रही है, जो अनवर डेवर का करीबी और विवेक अग्रवाल का भाई बताया जा रहा है।



चतुर्भुज राठी भाजपा के सक्रिय नेताओं में से एक : बताया जा रहा है कि कारोबारी चतुर्भुज राठी की कई कंपनियां संचालित हैं, जिनमें अमर इन्फ्रास्ट्रक्चर (अमर बिल्डकॉन), अमर महावीर कोल माइंस, अमर प्राइवेट लिमिटेड और टार कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड प्रमुख हैं। इन

कंपनियों का काम सड़क और पुल निर्माण जैसे सरकारी प्रोजेक्ट्स, शांतिग मॉल निर्माण और कोयला खनन से जुड़ा बताया जाता है। चतुर्भुज राठी भाजपा के सक्रिय नेताओं में गिने जाते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान उनके चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं रही थीं। वहीं, लोकसभा चुनाव

भाजपा-कांग्रेस के नेताओं के नाम शामिल : बता दें कि राज्य में निर्माणधीन भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए मुआवजा घोटाले में भाजपा-कांग्रेस के विधायक और दिग्गज नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इनकी भूमिका की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिन क्षेत्रों से यह प्रोजेक्ट गुजर रहा है, वहां दिग्गज नेताओं ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीन खरीदी। बाद में उन्हीं जमीनों का मुआवजा भी लिया।

पटवारी-आरखाई की भूमिका : पटवारी और आरखाई ने मुआवजे के प्रकरण बनाकर कलेक्टर को भेजे। जिन पर हस्ताक्षर के बाद मुआवजा जारी किया गया। इन नेताओं से जुड़े लोगों के ठिकानों पर ईडी ने 27 अप्रैल को छापेमारी की थी। वहां से कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिनसे नेताओं की कड़ियां जुड़ने के संकेत मिलते हैं। इसमें एक दिग्गज भाजपा नेता से संबंधित दस्तावेज भी शामिल बताया जा रहा है।

12 जिलों के कलेक्टर जांच के घेरे में : 12 जिलों के तत्कालीन कलेक्टरों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इनमें से 6 कलेक्टरों की सल्लिकता की आशंका जताई जा रही है, जिन पर मोटा कमीशन लेने का आरोप है। इनमें रायपुर, कोरा, धमतरी, बिलासपुर और दुर्ग के तत्कालीन कलेक्टरों के नाम सामने आए हैं। फकीर गण आरोपियों ने भी प्रस्ताव में इनका जिक्र किया है।

2024 के समय भी आयकर विभाग ने (ईओडब्ल्यू) ने सरकार के निर्देश पर उनके ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की थी।

ईओडब्ल्यू का दावा- राजस्व अधिकारियों ने किया घोटाला : आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा

(ईओडब्ल्यू) ने सरकार के निर्देश पर भारतमाला प्रोजेक्ट के मुआवजा घोटाले में एफआईआर दर्ज की है। इस मामले की जांच के बाद तत्कालीन एसडीएम निम्बू साहू समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

छत्तीसगढ़ में रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से 1.4 करोड़ ट्को 7 दिन डिजिटल अरेस्ट रही, टैर फंडिंग का डर दिखाया, जेल भेजने की धमकी दी

बिलासपुर, 30 अप्रैल 2026। बिलासपुर में साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड महिला प्रोफेसर को टैर फंडिंग का डर दिखाकर 7 दिनों तक 'डिजिटल अरेस्ट' रखा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट और ईडी के फर्जी नोटिस भेजकर ठगों ने महिला से 1 करोड़ 4 लाख 80 हजार रुपए चार अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए। ठग यहीं नहीं रुके, उन्होंने केस क्लोज करने के नाम पर 50 लाख रुपए की और मांग की और पैसे न देने पर बेटे-पोते को जेल भेजने की धमकी दी। ठगी का खुलासा तब हुआ जब डरी हुई प्रोफेसर ने मुंबई में रहने वाले अपने बेटे को फोन कर 50 लाख रुपए मांगे। बेटे को संदेह होने पर पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद सिविल लाइन थाना क्षेत्र की इस घटना पर रेंज साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ठगों ने महिला को सात दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। दरअसल के रिजल्ट हेवन निवासी प्रो. रमन



श्रीवास्तव (82) रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। वे डीपी कॉलेज में पदस्थ थीं, उनका बेटा प्रशांत श्रीवास्तव मुंबई में एचआर कंसल्टेंसी में डायरेक्टर हैं। 20 अप्रैल को उनके बैंक खाते पर अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को संजय पीएसआई बताया। पहले उसने रिटायर्ड प्रोफेसर को धमकाया और कहा कि वह एक प्रतिबद्धित संगठन (पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) को टैर फंडिंग कर रही है।

उड़ान में बिगड़ी यात्री की तबीयत, रायपुर में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग-बड़ा हादसा टला

रायपुर, 30 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ की राजधानी में गुरुवार को उस वक्त अफरा-तफरी का मौहौल बन गया, जब कोलकाता से पुणे जा रही एक फ्लाइट को मेडिकल इमरजेंसी के चलते बीच रास्ते में ही रायपुर एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। राहत की बात यह रही कि पायलट और क्रू की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार, फ्लाइट अपने तय समय पर कोलकाता से पुणे के लिए रवाना हुई थी। उड़ान सामान्य रूप से जारी थी, तभी अचानक एक यात्री की



तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई। यात्री की हालत देखकर विमान में मौजूद अन्य पैसेंजर्स भी घबरा गए। घटना के तुरंत बाद फ्लाइट के क्रू मेंबर्स ने यात्री को प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की। हालांकि, काफी प्रयासों के बावजूद

यात्री की हालत में सुधार नहीं हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए फ्लाइट को रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा। इमरजेंसी की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम को पहले से अलर्ट कर दिया गया था। जैसे ही विमान लैंड हुआ, मेडिकल स्टाफ तुरंत अंदर पहुंचा और बीमार यात्री को प्राथमिक उपचार दिया। प्राथमिक इलाज के बाद यात्री को बेहतर चिकित्सा के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया।

नक्सल संगठन में बड़ा अंदरूनी विवाद, आत्मसमर्पण करने वाले नेता पर नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी का तीखा हमलातीखा हमला

जगदलपुर, 30 अप्रैल 2026। बस्तर क्षेत्र में नक्सल मोर्चे से एक अहम घटनाक्रम सामने आया है, जहां माओवादी संगठन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा जारी ताजा बयान में आत्मसमर्पण कर चुके वरिष्ठ माओवादी नेता वेणुगोपाल देवजी पर कड़ा रुख अपनाया गया है। एनसीसी ने अपने प्रेस नोट में देवजी को संगठन से पूरी तरह अलग बताते हुए उन्हें विश्वासघाती करार दिया है। संगठन का कहना है कि उनके आत्मसमर्पण के बाद अब उनका माओवादी ढांचे से कोई लेना-देना नहीं रह गया है। इस बयान के बाद संगठन के भीतर चल रहे मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सूत्रों के अनुसार, देवजी के आत्मसमर्पण को लेकर पहले से ही असंतोष की स्थिति बनी हुई थी, जिसे अब सार्वजनिक बयान ने और स्पष्ट कर दिया है।

रायपुर में कंवल प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग फायर ब्रिगेड की टी बुझाने में जुटी, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

रायपुर, 30 अप्रैल 2026। रायपुर में गुरुवार सुबह विधानसभा थाना क्षेत्र के आमासिखनी स्थित कंवल प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। यह फैक्ट्री महालेखाकार कार्यालय के पीछे स्थित है। सुबह करीब 11 बजे धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और एहतियातना आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी।



फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां पहुंची : फायर ब्रिगेड की पांच से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। फैक्ट्री में प्लास्टिक सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैल गई और काले धुएँ का गुबार दूर तक दिखाई देता रहा। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब एक घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग को धीरे-धीरे नियंत्रण में लाया गया। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। हालांकि फैक्ट्री में रहे सामान और मशीनों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर

घटती घटना
संपूर्ण भारत के लिए एक प्रकाशन

रोजगार का सुनहरा अवसर

यौवक, कर्मठ एवं जुझारु महिला/पुरुष उम्मीदवारों से निम्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित है -

क्र. सं.	पद	संख्या	वेतन
01	समाचार संपादक	1 पद	₹10,000 से ₹15,000
02	प्रबंध संपादक	1 पद	₹10,000 से ₹15,000
03	विज्ञापन प्रभारी	2 पद	₹10,000 से ₹15,000
04	ब्यूरो चीफ	1 पद	₹10,000 से ₹15,000
05	संवाददाता	2 पद	₹8,000 से ₹12,000
06	कंप्यूटर ऑपरेटर	2 पद	₹8,000 से ₹12,000
07	कार्यालय अटेंडर	1 पद	₹6,000 से ₹8,000

विशेष निर्देश:

- कोन पद संकेत न करें
- इस एक उम्मीदवार स्वयं कोलेक्टर के साथ कार्यालय में उपस्थित हों

मौका न चूकें!

पता: कार्यालय - दैनिक समाचार पत्र "घटती-घटना" शनि मंदिर के पास, नन्दागढ़, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)

मोबाइल: **98265-32611**

इस सूचना को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जरूरतमंदों तक पहुंच सके!



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

सुशासन तिहार

2026

01 मई
से
10 जून
2026

गाँव-गाँव, द्वार-द्वार
सुशासन की सरकार



जिला स्तर पर लंबित प्रकरणों, जमीन संबंधी मामलों एवं प्रमाण-पत्र से जुड़ी समस्याओं का निराकरण

ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन

समस्याओं का त्वरित एवं समयबद्ध समाधान



विकास कार्यों को मिलेगी गति



जन-कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन



पारदर्शिता और जवाबदेही से 'जनकल्याण' होगा सुनिश्चित



उद्देश्य

संवाद से संपूर्ण समाधान

**अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं**